



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2017 ई0 (माघ 08, 1938 शक सम्वत्) [संख्या-04

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	117-170	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	23-28	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	01-08	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
शिक्षा (उच्च शिक्षा) अनुभाग-06

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 1289/XXIV(6)/2016-11(4)/2015-श्री राज्यपाल महोदय, रास बिहारी बोर सुभारती विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35, वर्ष 2018) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

एस० रामास्वामी,

मुख्य सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

04 जनवरी, 2017 ई०

संख्या 15/XII(1)/2017-92(20)/2014 T.C.-I-उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 की
धारा 4(4) एवं जिला योजना समिति नियमावली, 2010 के नियम 4(7) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला योजना समिति
की धारा 4, धारा 6 की उपधारा 3 एवं धारा 7, 9, 12 व धारा 15 की उपधारा 3 तथा उत्तराखण्ड जिला योजना समिति संशोधित
अध्यादेश 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार पंचायतीराज अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 316/XII(1)/15-92(05)/2007,
दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से समस्त जनपदों में जिला योजना समिति में सदस्य नामित किये गये थे।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से नामित किये गये सदस्यों को पूर्व की भाँति जिला योजना समिति में
यथावत् सदस्य नामित किए जाते हैं।

3. जनपद हरिद्वार में पूर्व सदस्यों का नामांकन निरस्त करते हुए जिला योजना समिति में निम्न सदस्यों को
नामित किया जाता है:-

जनपद-हरिद्वार

1. चौधरी सत्यजीत सिंह, लक्सर, जनपद हरिद्वार,
 2. सुश्री ईशा त्यागी, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार,
 3. श्री विनोद कुमार, दरगाहपुर, जनपद हरिद्वार,
 4. श्री तबरेज आलम, हरिद्वार ग्रामीण, जनपद हरिद्वार,
 5. डा० एस० पी० भाबरा, झबरेड़ा, जनपद हरिद्वार,
 6. श्री सोनी चौहान, धारीवाला, जनपद हरिद्वार।
4. उक्त के अतिरिक्त जिला योजना समिति में शेष निर्वाचित/आमंत्रित सदस्य यथावत् बने रहेंगे।

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव।

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1

आदेश/पदोन्नति

23 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 1464/Xiv-1/2013-3(54)/2016-सहकारिता विभाग में सहायक निबन्धक (वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निबन्धक, सहकारिता (वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को उप निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 295/2016/XXVII(9)/यू०ओ०-04/स्टाम्प/2014-श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय-समय पर यथासंशोधित की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वयं सहायता समूहों द्वारा बैंकों से ₹ 5.00 लाख तक प्राप्त किए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में निष्पादित बन्धक विलेखों पर प्रमार्य स्टॉम्प शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यालय-ज्ञाप

03 जनवरी, 2017 ई०

संख्या 01/XXXIV/2017-31/2014-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई०सी०टी० एवं ई०) के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा अनुकूल व्यवसायी वातावरण बनाने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय, राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (आई०सी०टी० एवं ई०) नीति 2016-25 (उत्तराखण्ड राज्य), जिसकी प्रति संलग्न है, को तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक नीति

वर्ष 2016-2025 (उत्तराखण्ड राज्य)

विषय सूची

अध्याय-1 प्रस्तावना	पेज नं०
भूमिका	121-122
सामान्य	122-123
राष्ट्रीय उद्देश्य	123-124
दृष्टिकोण	124
लक्ष्य	124-125
मिशन	125
उद्देश्य	125-126
अध्याय-2 कार्यान्वयन रणनीति	
रणनीति प्रेरित करना	127
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति का कार्यान्वयन	127-133
इलेक्ट्रॉनिक पद्धति डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) नीति का क्रियान्वयन	133-135
ग्रामीण बीपीओ/केपीओ उद्योग	135
डाटा केन्द्र तथा डाटा केन्द्र पार्क	135
अध्याय-3 प्रोत्साहन	
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति (एनईपी) 2012 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन	136-137
क्षेत्रों का विभाजन	137-138
उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन	138
वित्तीय प्रोत्साहन	138-140
गैर वित्तीय प्रोत्साहन	140-141
बुनियादी सुविधाओं का समर्थन	141
अध्याय-4 अनुश्रवण और निष्पादन	
परिशिष्ट-क	142-147

अध्याय -1 - प्रस्तावना

भूमिका

- 1- भू-मण्डलीय आर्थिकी आधारित ज्ञान को बढ़ाने का मुख्य संचालक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में इसके वर्तमान भू-मण्डलीय स्तर प्रदान करने के लिए भारत की स्थिति और उसकी सक्षमता इसे अंत तक पहुंचाने में सहायक है। विकास और प्रसार के लाभों की पहुंच के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की नीतियां तथा कार्यक्रम औद्योगिक एवं विकासशील देशों में तैयार की जा रही है।
- 2- प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स में वृद्धि कर रही है। यह क्षेत्र सामान्य, रणनीतिक और महत्वपूर्ण रूप में है। समस्त विकासशील और विकसित देश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के महत्व को समझ रहे हैं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के विकास के प्रसार को नीतियों और संयुक्त लोक निजी कार्यक्रमों के द्वारा प्रयोग कर रहे हैं। विकासशील देशों में भी यह स्थापित हो चुका है कि उद्योगों, संरचनात्मक आधारित आधुनिकता और सेवाओं के प्रतियोगी वृद्धि, समूची सूचना की कमी को कम करने और समूचे आर्थिक मूल्यों के व्यवहरण को न्यून करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की सार्थकता है। ये देश मुख्य क्षेत्रों में जैसे मेको आर्थिकी योजनाओं और निर्णय करने, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, विनिर्माण, वित्त और बैंकिंग, परिवहन, वाणिज्य, प्रकाशन, विद्युत संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स का प्रयोग कर रहे हैं।
- 3- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केन्द्र यथा बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे तथा एनसीआर जिनके निकट भारत में कुल सूचना संचार प्रौद्योगिक उद्योगों के लगभग 90 प्रतिशत अवस्थित हैं और अग्रेत्तर विस्तार के लिए संरचनात्मक तथा मानव संसाधन बाधाओं की चुनौतियां हैं। यह आवश्यकताएं भारतीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के लिए अनन्य क्रियान्वयन को घटाने के लिए उत्तराखण्ड के शहरों में टियर दो तथा टियर तीन में बदले जाने है। भू-मण्डलीय वातावरण के कम में यह कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य में इसे समय से प्रारम्भ किया जाय और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के महत्वपूर्ण लाभों को उसके अधिवासियों को पहुंचाने के उद्देश्य से शीघ्र कदम उठाने होंगे।
- 4- शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास, वित्तीय संसाधन, रोजगार सृजन, सुशासन इत्यादि में आने वाले विभिन्न विकासीय चुनौतियों की शाखाओं को प्रौद्योगिक सक्षमता के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति आर्थिकी में बहुत बड़े मामले में दक्षता ला सकती है। उत्तराखण्ड राज्य नीति दो लक्ष्य, राज्य की पहुंच के भीतर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की पूर्ण शक्ति को लाना और राज्य के मानव संसाधन तथा क्षमता का कवच है जिससे 2025* में सूचना संचार उद्योगी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवाओं के लिए भू-मण्डलीय/राष्ट्रीय हब तथा गंतव्य के रूप में उत्तराखण्ड को पहुंचाया जा सके।
- 5- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स नीति राज्य में इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकाईयों के

संस्थापन के लिए निजी सहभागियों में वृद्धि करना और सूचना प्रौद्योगिकी के समाधान उपलब्ध कराना, सभी आर्थिक क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक की तैनाती हो सके। इस नीति का उद्देश्य राज्य के भीतर विभिन्न लाभार्थियों की ओर से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहभागिता के माध्यम से कार्रवाई हो।

- 6- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रसार के अतिरिक्त भारत सरकार की ओर से जारी "मेक इन इंडिया के' की छत्री के अधीन राज्य के भीतर इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकाइयों को संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इससे वर्तमान में पूर्व निर्यातित होने वाली विभिन्न घटकों के मूल्य में कमी आ सकेगी। इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग इलेक्ट्रानिक्स पद्धति आरेखण तथा विनिर्माण जिसमें सेमी कन्डक्टर डिजाइन, उच्च स्तरीय विनिर्माण, इलेक्ट्रानिक घटक, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पाद के लिए इलेक्ट्रानिक पद्धति डिजाइन, टेलीकॉम उत्पाद तथा उपस्कर, संचार प्रौद्योगिकी पद्धति तथा हार्डवेयर से संरचित होगी। इलेक्ट्रानिक उद्योग विश्व में सबसे बड़ी और सबसे तीव्र वृद्धि वाली विनिर्माण उद्योग है जिसमें यूएसडी 1.75 ट्रिलियन बतायी गई है। इसके वर्ष 2020 तक यूएसडी 2.4 ट्रिलियन पहुंचने की सम्भावना है।
- 7- मुख्य लाभंशी- मुख्य लाभंशी राज्य में केवल आईटी0 विभाग (आईटी0डी0ए0/आईटी0 निदेशालय तथा एस0ई0एम0टी0 सहित) ही नहीं है वरन् पुलिस विभाग, विभिन्न संगठनों के उद्योग प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा के अधीन सभी संस्थाएं/विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और राज्य के नागरिक भी सम्मिलित हैं।
- 8- राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति के अनुसार राज्य को चार भागों में विभक्त किया गया है जिसे धारा 3 में उल्लिखित किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स संरचना के विस्तार के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रोत्साहन बल प्रदान करेंगे।

सामान्य

- 9- उत्तराखण्ड जब वह उत्तरी उत्तर प्रदेश का भाग था, जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को हुआ था। हिमालयन पर्वत श्रृंखला के तलहटी पर इसका अधिकतर भू-भाग स्थित है, इसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.08 करोड़ है और भौगोलिक आकार में इसकी परिधि 53483 वर्ग मीटर है, जिसमें से लगभग 88 प्रतिशत भू-भाग पर्वतीय क्षेत्र का है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों का भण्डार है जिसमें विशेषकर जल और जंगल जिसमें ग्लेशियर, नदियां, जंगल और पर्वत चोटियां हैं। यह वास्तव में देवभूमि है।
- 10- उत्तराखण्ड सरकार इसके नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया है जिससे समाज में तेजी और आर्थिक विकास लाने, सरकार के निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न उपभोगताओं के मध्य दक्षता के माध्यम से आदर्श ईसोसाईटी माडल को सभी प्रकार से नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिक तकनीकी को तेजी से अंगीकार करने, रोजगार का सृजन करने, मूल्य को प्रभावी करने, सूचना का जाल बिछाने, ईको के प्रति सजग रहने और वर्ष दर वर्ष इसके उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक पद्धति आरेखण और विनिर्माण में यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2012 के अनुसार वर्ष 2020 तक इसमें 400 बिलियन डालर की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है और इससे लगभग 28 मिलियन कुल

रोजगार सृजित होंगे।

- 11- इस अभिलेख का यह उद्देश्य है कि सभी सन्दर्भों में राज्य में सभी उन्नति की प्राप्ति के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स के प्रबंधन और प्रभावी कार्यक्रम के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराना है। इस नीति के अभिलेख उत्तराखण्ड एमएसएमई नीति, 2015 एवं उत्तराखण्ड मेगा औद्योगिक एवं विनिवेश नीति, 2015 के विस्तारित अभिलेख होंगे।
- 12- राज्य के भीतर की गई उन्नति के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् इस नीति अभिलेख को पुनर्विलोकित किया जायेगा और उसके पश्चात् उसमें आवश्यक संशोधन किये जायेंगे। यहां पर यह भी कहना है कि सम्पूर्ण राज्यों और भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलना में और श्रेणी, की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को तैयार रखने विभिन्न पहलुओं की रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए सम्बंधित विभिन्न ई-शासन सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा उसके उन्नयन के सम्बंध में त्रैमासिक आधार पर एनईजीडी की अनुपालन करेगी। सभी विभागों से यह अनुरोध है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए उससे सम्बंधित विभागों के भीतर विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी से सम्बंधित कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

राष्ट्रीय उद्देश्य

- 13- यह अनिवार्य है कि राज्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स नीति के मामले में राष्ट्रीय नीतियों के साथ संपर्क बनाये रखें। इस दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी 2012 (एनपीआईटी 2012), ईएसडीएम पर राष्ट्रीय नीति 2012, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति, 2012 (एनईपी 2012) और राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति, 2012 (एनटीपी 2012) को इस अभिलेख में सम्मिलित किया गया है और निम्नवत संक्षेप में प्रस्तुत है-

- क. वर्तमान 100 बिलियन को 300 बिलियन यूएस डालर तक सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक के राजस्व को बढ़ोतरी करने के लिए, व निर्यात 69 बिलियन से बढ़ाकर वर्ष 2020 में 200 बिलियन यू. एस. डालर करना।
- ख. उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में महत्वपूर्ण वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए,
- ग. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में आर एण्ड डी एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,
- घ. महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में सुधार के लिए आईसीटी को अभिग्रहण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए,
- ङ. मूल्य सृजन में आई.टी के अभिग्रहण के लिए एसएमई और स्टार्टअप के लिए चालू वित्त वर्ष में लाभ प्रदान करने के लिए,
- च. 10 मिलियन आईसीटी में अतिरिक्त कुशल जनशक्ति का पूल बनाने के लिए,
- छ. प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को ई-साक्षर बनाने हेतु। उत्तराखण्ड राज्य में सभी निवासियों को ई-साक्षर बनाने के लिए 2025 तक प्रयास करेंगे।
- ज. इलेक्ट्रानिक मोड में सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए अनिवार्य वितरण और किफायती उपयोग प्रदान करने के लिए,

- झ. सरकार में और विशेष रूप से पारदर्शिता, जवाबदेही, क्षमता, विश्वसनीयता और विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में,
- ञ. शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और वित्तीय सेवा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की पहल के लिए आईसीटी का लाभ उठाने, इक्विटी और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए,
- ट. भाषा प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भारत वैश्विक हब बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और समस्त भारतीय भाषाओं में सुलभ सामग्री के विकास की सुविधा तथा इस तरह के डिजीटल डिवाइस से मदद करने के लिए,
- ठ. समावेशी विकास को बढ़ावा के लिए अलग विकलांग लोगों द्वारा सामग्री और आईसीटी अपनप्रयोगी के उपयोग को सक्षम करने के लिए,
- ड. कर्मचारियों की संख्या का विस्तार और जीवन भर सीखने को सक्षम करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए,
- ढ. एक सुरक्षित और कानूनी तौर पर शिकायत साइबरस्पेस पारिस्थितिकी यंत्र सुनिश्चित हेतु नियामक और सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए,
- ण. खुले मानकों को अपनाने और खुले स्रोत तथा खुले प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए,
- त. देश में एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा ईएसडीम क्षेत्र के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2020 में विभिन्न स्तरों पर लगभग 28 लाख लोगों के लिए यूएसडी 100 विलियन का निवेश और रोजगार को शामिल करके 400 विलियन यूएसडी के कारोबार को हासिल करने के लिए,
- थ. वर्ष 2020 तक यूएस डालर 55 विलियन के कुल वार्षिक आय व्यय को प्राप्त करने, अन्य उन्नत तकनीकी क्षेत्रों तथा चिप डिजाइन, बहुत बड़ी मात्रा में एकीकरण में भू-मण्डलीय नेतृत्व प्राप्त करने के लिए साफ्टवेयर उद्योग को स्थापित करने और आकस्मिक चिप डिजाइन को तैयार करने के लिए,
- द. वर्ष 2020 तक 60 प्रतिशत से अधिक वर्तमान 20से 25 प्रतिशत को वृद्धि करने के लिए इन पहलुओं के वास्तविक उपलब्धता को तैयार करने के लिए कच्चे माल, भाग और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को कमबद्ध रूप से मजबूती से आपूर्ति के लिए तैयार करने हेतु,
- ध. वर्ष 2020 तक 5.5 विलियन यूएस डालर से 80 विलियन यूएस डालर तक ईएसडीम के भाग में निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए,
- न. ईएसडीएम क्षेत्र में अच्छी मानव शक्ति की उपलब्धता के लिए विशिष्ट लोगों का चयन करने, सम्बंधित विषय में स्नातक डिग्री को देने के लिए विशेष ध्यान आकर्षित करने तथा वर्ष 2020 तक लगभग 2500 शोधार्थियों को तैयार करने के लिए।

दृष्टिकोण

- 14- समावेशी विकास के साथ उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास के लिए एक वाहन के रूप में आईसीटी और ई का उपयोग करने के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ एक जीवंत समाज बनाने के लिए।

लक्ष्य

- 15- उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतया डिजीटाइज्ड और नेटवर्क समाज बनाने के लिए जहां राज्य के आर्थिक विकास सम्भव हो सके, हेतु प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की पहुंच तक उपलब्ध होने तथा सूचना की प्रवाह हो, को तैयार करना है।

- 16— रोजगार सृजन— (राष्ट्रीय औसत से अधिक) 78.82 प्रतिशत की शुद्ध उच्चतर शैक्षणिक दर को दिये जाने, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी को कम करने के सरकार के उद्देश्य तथा उत्तराखण्ड में उनके उपक्रमों को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रानिक विनिर्माण उपलब्ध कराना है।
- 17— राज्य के लिए मुख्य बढोतरी के रूप में इलेक्ट्रानिक्स तथा इलेक्ट्रानिक पद्धति आरेखण एवं विनिर्माण उद्योगों में विनिवेश हेतु उत्तराखण्ड राज्य अत्यधिक प्राथमिकता देने वाला राज्य है।

मिशन

18— इस नीति का मिशन है कि —

- क. भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स को आकर्षित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति,
- ख. उत्तराखण्ड के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स की उपलब्धि के लिए मुख्य साधन बनाने,
- ग. सहयुक्त समुदायों को भौतिक समुदायों में बदलने के लिए जिससे कि वास्तविक आर्थिक उन्नति तथा जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके।

उद्देश्य

- 19— अनुकूल उद्योग मित्रता और सक्रिय वातावरण देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक कम्पनियों के लिए आकस्मिक विनिवेश प्रक्रिया के रूप में उन्नयन करना,
- 20— राज्य में संरचनात्मक कला के अधिष्ठापन राज्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक स्थल के रूप में राज्य के शहरों / कस्बों में अनुकूल वातावरण तैयार करना। राज्य के भीतर एकल खिडकी सहायता उपलब्ध कराने के माध्यम से इसकी पूर्ति की जायेगी।
- 21— किसी स्थल पर निर्वाद संयोजन उपलब्ध कराने के रूप में विश्व स्तरीय सूचना और प्रौद्योगिकी संरचना सृजन हेतु व्यापारियों और उपभोक्ताओं, सूचना प्रौद्योगिकी संचालकों के जीवंत इको-पद्धति की संरचना में लोक और निजी सेवाओं के उपयोग को आसान करने, सेवा उपलब्ध कराने वाले, सरकार, संचालन और इसके अंतिम उपभोक्ता ओ उपलब्ध कराना। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसीएस) को स्थापित करने की योजना बनाना,
- 22— इस उद्योग में रोजगार के लिए उन्हें नियोजित करने के रूप में युवाओं के शक्ति और ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्कूल, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में तेजी लाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग हेतु अपेक्षित विकसित मानव शक्ति और उसका उन्नयन,
- 23— सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सहयोगी पद्धति निर्णय और प्रबंधन के लिए यंत्र के रूप में दिया जाना ही नहीं है वरन् नागरिकों को अधिक उपयोगिता, पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार की प्रक्रिया में पुनर्निर्माण भी है। उत्तराखण्ड की सरकार इसके सभी कृत्यों

में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुपालन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए;

- 24— सूचना प्रौद्योगिकी के मामले को उपभोक्ता तक आसान पहुंच बनाये जाने के लिए राज्य के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति करना,
- 25— राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक के उन्नयन के लिए जीडीपी संचालन के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स प्रयोग के लिए युवाओं हेतु रोजगार सृजन के दृष्टिगत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स स्थल के रूप में आकर्षित करने के लिए इस क्षेत्र की आय क्षमता को बढ़ाने तथा साथ ही साथ इस क्षेत्र में घरेलू राजस्व मात्रा को निर्यात करने के लिए,
- 26— ईएसडीएम के सम्पूर्ण मूल्यांकन क्रम में अनुकूल विनिवेश मित्रता सम्बन्ध को सृजित करने के माध्यम से इलेक्ट्रानिक के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोन्नत करना,
- 27— राज्य में आरएनडी के जीवंत ईको पद्धति के विकास को प्रोन्नत करने के लिए, आरेखण और इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रानिक के 'अविष्कार' करने के लिए इसमें अनिवार्यता महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार द्वारा उसके भीतर किया जाना,
- 28— राज्य के भीतर प्रति वर्ष राज्य के अधिवासियों को 8000 से 10000 तक के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन का लक्ष्य,
- 29— वर्ष 2019 तक 15000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और ईएसडीएम के क्षेत्र में बौद्धिक विकास में राष्ट्रीय नीति के अधीन आवंटित रिकित्तियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति के लागू होने /विस्तारित करने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उस पर आधारित होगी।

अध्याय-2 —कार्यान्वयन रणनीति

रणनीति प्रेरित करना

1- यहां प्रेरणा की 6 रणनीतियां हैं जिसके तीन स्तम्भ तीन भूमिकाओं द्वारा सहयोजित है। तीन स्तम्भों में आर्थिक व्यवहरण, लोक शक्ति और प्रबंधन तथा अविष्कार सम्मिलित है जिसमें संरचना विकास, मानव विनिवेश विकास और डिजिटल भाग सम्मिलित करते हुए मजबूत इरादे सहयोग दिए जाने की आवश्यकता है। यह सभी 6 प्रेरणाएं उत्तराखण्ड राज्य के लिए बढ़ोतरी हेतु इंजन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक के आकस्मिक नेतृत्व करेंगे। भारत में अत्यधिक वरिय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक स्थल के रूप में उत्तराखण्ड की मान्यता तथा राज्य के अधिवासियों के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता के सुधार में परिणाम के अनुरूप कार्य करना है। राज्य सरकार देहरादून में विद्यमान आईटी पार्क के अतिरिक्त द्वितीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा की स्थापना करने की परियोजना भी बना रहा है। उत्तराखण्ड की सरकार राज्य में ठंडे मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में डाटा सेंटर कलस्टर को स्थापित करने की योजना बना रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा हब तथा डाटा सेंटर कलस्टर आगामी दो वर्षों के भीतर स्थापित करने की योजना है और इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शासित किया जायेगा।

2- आईटी बजट का निर्धारण: राज्य के सभी विभाग सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के सृजन और बढ़ावे के लिए उसके वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत सुरक्षित रखेंगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नीति का कार्यान्वयन

3- आईसीटी के माध्यम से सुशासन

क. इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि लोगों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रभाव का संयुक्त प्रभाव मुख्य रूप से सुशासन है, उत्तराखण्ड की सरकार सैद्धान्तिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं लोगों की समस्याओं को सरल बनाने और सरकार के साथ व्यवहरण के द्वारा प्रौद्योगिकी सहयोग से राज्य के विकास के लिए कार्य करेंगी और आईसीटी के प्रभावी प्रयोग में लोगों के मध्य समुचित कौशल का निर्माण करेगी। राज्य उसके नागरिकों के संशक्ता के लिए यंत्र के रूप में सूचना का प्रयोग करेगी।

ख. जैसा कि राज्य में कारपोरेट, सहयोग और विभिन्न विभागों के मध्य समेकित सूचनाओं और उसके केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार का एक लक्ष्य निर्धारित है जिससे कि नागरिकों, व्यापार और अन्य सरकारी विभागों को त्वरित रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता दिये जाने हेतु एक रीति जिससे कि विभिन्न विभागों के मध्य विभिन्न अंतर्सम्बंधी सेवाओं की सरकारी प्रक्रियाओं और समेकन को सरल किया जा सके।

ग. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2018 तक इलेक्ट्रानिक रीति के माध्यम से नागरिक केन्द्रियक सेवाओं के अधिकतर मामले उपलब्ध कर दिये जायें। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य ई-डिस्टिक और अन्य रीति के परियोजनाओं को खड़ा करेगी जो कि मार्ग में उपलब्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी एक एकल पोर्टल से इन परियोजनाओं के माध्यम से नागरिक केन्द्रियक सेवाओं की पारदर्शिता

और दक्षता को प्राप्त किया जाय।

घ. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2018 के अंत तक सभी आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड किया जाना है। इस समय सरकार की योजना पेपर मुक्त होना है। सभी सरकारी विभागों में ईआरपी पद्धति जिसमें एचआरएमएस, ईआफिस, ईफाइल सम्मिलित है, क्रियान्वित होंगी। इस प्रयोजन के लिए सभी अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर/ईहस्ताक्षर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ड. सुरक्षित मीडिया पर जहां नागरिक व्यक्तिगत अभिलेख सुरक्षित कर सकता है, में डिजिटल लाकर के प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जायेगा और प्रमाणित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के अपेक्षा जहां अपेक्षित हो, विभिन्न अभिकरणों के साथ उसे सहभागी या उसी अनुरूप किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया उन सभी सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी जो इस सुविधा को प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देगा।

च. ई-गवर्नेंस के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य यह विश्वास करता है कि वह अपने नागरिकों को कोई सरकारी सेवा किसी भी समय, किसी स्थान पर प्रदान कर सकता है। विकल्प नागरिकों का होगा न कि सरकारी विभागों का। राज्य सीएससी/इंटरनेट के माध्यम से ऐसी सेवाओं को उसके प्रशिक्षण कर्ताओं द्वारा अधिरोपित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से कर सकेगा।

छ. राज्य सरकार की समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सर्वोत्तम औद्योगिक व्यवहारों और निर्देशों के आधार पर नये सृजन प्रौद्योगिकी आत्मक्षात करने की योजना है। राज्य सरकार बहुमूल्य आंकड़ों के होने की बावत जोखिम घटाने के लिए सरकार के सभी विभागों के भीतर साईबर अनुशासन स्थापित करेगी।

ज. विशेष जोर उपयोगकर्ता को प्ररूप या रीति से प्रौद्योगिकी मामलों के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने के लिए आसान और सुविधाजनक होगा। यंत्रों को चुनने के लिए कम्प्यूटर्स, टेलीफोन्स, डिजिटल टीवी, मोबाईल यंत्र, किओस्क, वैयक्तिक डिजिटल सहायता इत्यादि को सहयोगी व्यवहरण की यंत्र उपयोगिता के अध्यधीन रहते हुए ऑनलाईन पहुंच की सुविधा को सृजित और संरचनात्मक सहयोग के लिए विचार किया जायेगा। राज्य योजना निम्नलिखित मामलों पर कार्य करेगी—

एक— नागरिकों को यंत्रों (इंटरनेट/ब्राडबैंड की पर्याप्त पहुंच) के लिए केन्द्रीय सरकारों के अभिकरण, बैंकिंग/ वित्तीय अधिष्ठान और एनजीओ से समन्वय करना;

दो— सरकारी अधिकारियों और संबंधित सूचनाओं को नागरिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के कम में राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सामान्य सेवा केन्द्रीय योजना के माध्यम से सभी ग्रामों में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित कर रही है। ये सामान्य सेवा केन्द्र सरकार और उसके विभिन्न कार्यालयों को सामान्य पहुंच बिन्दु के रूप में सेवाएं देगी;

तीन— सरकार विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभार्थियों के केन्द्रीय उत्तरदाता के रूप में सभी अन्य आवेदककर्ताओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी राज्य अधिवासियों के डाटा आधारित परियोजना को तैयार किया जायेगा। यह आंकड़े अभिप्रमाणन और उसकी दो बार की सेवाओं को रोकने में आधार को संयोजित किया जायेगा। यह आंकड़े सरकारी योजनाओं में बाह्यस्त्रव को रोकने में मदद करेगा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मामले में निर्णय लिये जाने पर भी सहयोग करेगा। यद्यपि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ-साथ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी

व्यक्तियों के आंकड़े गोपनीय रखने के लिए कार्य करेगा। प्रारम्भ में निम्नलिखित विभाग आधार से जोड़े जायेंगे—

- समाज कल्याण विभाग
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- शहरी विकास विभाग
- विद्यालयी शिक्षा विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- तकनीकी शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- राजस्व विभाग
- सेवायोजन विभाग

झ. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नागरिकों को उनकी सेवाओं को दिए जाने की गति प्रदान करने के उद्देश्य से इन विभागों के आंतरिक सक्षमता को सुधारने हेतु अवसरों को चिन्हांकित करने हेतु राज्य में अन्य विभागों के साथ निकटता से कार्य करेगा।

ज. पर्वतीय जिलों के लिए कठिन पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने के कम में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आईसीटी सम्भाल सकेगा। आईसीटी आपदा प्रबंधन विभाग को भी मजबूत करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा।

4— प्रभावी आईसीटी संरचना का निर्माण

क. राष्ट्रीय आईसीटी नीतियों का समर्थन

एक— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के ई-गवर्नेंस योजना के अधीन विभिन्न प्रोत्साहन केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसरण में स्वान, सीएससी, एसडीसी इत्यादि से सहयोग करेगा। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहयोग के अतिरिक्त, अतिरिक्त विनिर्माण के आवश्यकता पर राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

दो— स्वान: संबंधित ब्लाक मुख्यालय/तहसील मुख्यालय तथा सभी 13 जिलों मुख्यालयों के साथ राज्य मुख्यालय से सम्बंधित स्थानों में यह प्रभावी है।

तीन—सीएससी: — वहन योग्य मूल्य पर नागरिकों के द्वार पर समेकित रूप से सभी सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करने के दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना तैयार की थी। सामान्य सेवा केन्द्रों, आईसीटी सक्षम केन्द्रों के अधीन सभी जिलों को आच्छादित करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण भारत में सूचना और सेवाओं को किसी भी समय किसी भी स्थान पर वैबसाइट के माध्यम से पहुंचाने के लिए सृजित किया जायेगा।

चार— एसडीसी:— जीटूसी और जीटूबी की इलेक्ट्रानिक प्रदाता को सेवाओं के समेकन, आवेदन और संरचना उपलब्ध करायी जायेगी। यह सभी सरकारी विभागों के आंकड़ों, आवेदन सेवाओं, वैब

सरवर और मेल सरवर पर रखी जा सकेगी। आईटी पार्क, देहरादून में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी भवन में राज्य का एसडीसी अवस्थित किया जाएगा।

ख. प्रौद्योगिकी- वास्तुकला और मानक

एक- 24 × 7 गुणवत्ता की सेवाओं के माध्यम से प्रभावी पीपीपी मॉडल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सृजन और सेवाओं को प्रदान किए जाने तथा अवरोध मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए अभिप्रमाणन और भुगतान सेवाओं, नेटवर्क प्रदाताओं, संरचनात्मक प्रबंधन सेवाओं के रूप में सेवा लेने वाले, सरकारी सेवाएं और अन्य तृतीय पक्षकार की सेवाओं के रूप में सेवा सृजन और उसके प्रदान किए जाने के लिए विभिन्न कार्यों में भूमिका दिए जाने के लिए सम्यक् मान्यता देने हेतु ई-गवर्नेंस वास्तुकला को विकसित करना है।

दो- केन्द्र द्वारा आत्मक्षात किए जाने वाले कार्य पर आधारित राज्य भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यथासंस्तुत आंकड़े और महाआंकड़े आपसी आदान प्रदान से सम्बंधित उनके ई-गवर्नेंस मानकों को बाध्यकारी रूप से जैसा और जहां यह मानक जारी किए जायें, अनुसरण और लागू करेगा।

तीन- उत्तराखण्ड सरकार तकनीकी दृष्टिकोण से तटस्थ है किन्तु उसके एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि किसी साफ्टवेयर पर उसके मानकों का आधार तथा उसके आंतरिक मानक परिभाषित हों। इसलिए उत्तराखण्ड की सरकार पारदर्शी मानकों पर कार्य करेगी।

चार- सरकार किसी प्रौद्योगिकी/वेन्डर स्थल के होने वाले निशुल्क आवश्यकता को मान्यता देने तथा प्रौद्योगिकी और वेन्डर को आपस में मिलाते हुए आगे बढ़ाने के लिए इन वेन्डर/सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहयोग करेगी। यह नये प्रौद्योगिकी को लाने में आवश्यक कदम उपलब्ध करायेगा। यह योजना नागरिकों के लिए सेवाओं के देने में निजी सहभागिता के लिए तत्पर है।

ग. नेटवर्क/ संचार संरचना

एक- तारतम्यता के सृजन में ई-गवर्नेंस प्रारम्भ करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। स्वान राज्य के बाहर तारतम्यता के लिए पूर्व से स्थान रखती है। स्वान के दिशा निर्देश और केन्द्र के सहयोग से संचार संरचना के लाभ को पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जायेगा। सरकार अन्य लोक और निजी नेटवर्क को प्रदूषण मुक्त किए जाने के लिए बैण्ड विथ उपलब्धता को सृजित करके बढ़ायेगी और प्रतियोगिता के माध्यम से मूल्यों को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगी।

दो- स्वान के अधीन ऊर्ध्वाकार संयोजिकता के माध्यम से राज्य का सभी सरकारी विभागों को संयोजिकता उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

तीन- राज्य का भारत सरकार की परियोजना एनओएफएन के कियान्वयन के माध्यम से 2017 के अंत तक ग्राम पंचायत स्तर पर संयोजिकता प्रदान करने का लक्ष्य है। राज्य योजनाओं के लिए अपेक्षित समयवद्ध अनुमोदन और अन्य कोई आवश्यकता उपलब्ध कराते हुए इस परियोजना के तीव्र गति से कियान्वयन में सहयोग देगी।

चार- राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य चरणवद्ध रीति से राज्य के पर्यटक/तीर्थ स्थानों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

घ. मोबाइल संचार : प्रौद्योगिकी के विकास, आकड़ों की खपत की मात्रा, टेली स्थल की बढ़ती तथा स्मार्ट फोन के बड़ी संख्या में बढ़ती को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक मात्रा में टावर को स्थापित किया जाना आवश्यक है। किसी मोबाइल नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर की संख्या की अपेक्षा होती है और इनके न होने पर मोबाइल आच्छादन में कमी, सेवाओं में न्यूनता, न्यून इंटरनेट गति और कॉलड्रॉप जैसी समस्याएं आती हैं। उत्तराखण्ड राज्य का दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र मोबाइल संयोजिता से अभी आच्छादित नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा से वंचित होना पड़ता है। राज्य सरकार इसके लिए सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन देगी। राज्य सरकार सरकारी विभागों को भी इस हेतु प्रोत्साहित करेगी। सरकार मोबाइल टावर की स्थापना के लिए सरकारी भवनों और भूमि का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

5- मानव कौशल विकास

क. आईसीटी के क्षेत्र में राज्य सरकार कौशल विकास के लिए विशेष रूप से युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, औद्योगिक कर्मचारियों, ग्रामीण समुदायों जिसमें महिलाएं सम्मिलित हैं, को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए नागरिकों की क्षमता का निर्माण – रोजगार अवसर के सृजन हेतु शक्ति प्रदान करना है।

ख. सक्षमता निर्माण प्रयोग के भाग के रूप में उत्तराखण्ड की सरकार का वास्तविक कम्प्यूटर/डिजिटल जानकारी प्रदान किया जाना उसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड की सरकार राज्य के सभी विद्यालयों में डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहती है। विभिन्न अन्य मामले रूसा और रूसो के अधीन कम्प्यूटर/डिजिटल ज्ञान के क्रियान्वयन को बढ़ाना चाहती है। राज्य विद्यमान औद्योगिक संस्थानों, पालिटेक्निक संस्थाओं और सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ उत्तोलन करना चाहेगी।

ग. राज्य विद्यमान तकनीकी संस्थाओं और निजी फार्मर्स उत्तोलन करेगी और आर तथा डी प्रयास से समन्वय स्थापित करेगी जिससे कि आम जनमानस को लाभ हो।

घ. (राज्य सरकार के विद्यालयों/महाविद्यालयों) से उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक छात्रों से समुचित आईसीटी कौशल की अपेक्षा की जानी चाहिए। आईसीटी आन्दोलन, स्कूल और विद्यालयों में तेज गति के प्रभाव के दृष्टिगत उनके जीवन वृत्त में इन्हें शामिल करने के लिए प्रेरणा दी जायेगी।

ड. सरकार के भीतर सक्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित होगा। इसमें प्रोग्राम, प्रबंधन, व्यापार प्रक्रिया अभियंत्रणीय, प्रबंधन परिवर्तन, वास्तुकला आरेखण इत्यादि के रूप में विभिन्न कौशल स्तरों के लिए वाह्यस्त्रों और आंतरिक स्त्रों को सम्मिलित किया जायेगा। विभिन्न विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से ई-गवर्नेंस के संचालन के लिए कार्यवाही की जायेगी और सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के लिए अधिक योजनाबद्ध तरीको से प्रशिक्षण दिया जायेगा। उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के लिए राज्य में नेतृत्व विकास हेतु सेमिनार का आयोजन किया

जायेगा जिससे आईसीटी के बारे में जागरूकता लायी जा सकेगी जिससे वह प्रत्येक प्रश्न पर सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सके।

च. प्रत्येक नये सरकारी अधिकारी को प्रथम वर्ष में आईसीटी पर 15 दिनों की बाध्यकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इन पाठ्यक्रमों में मध्यम स्तरीय कम्प्यूटर ज्ञान प्रशिक्षण, तीन दिनों का पुनः पाठ्यक्रम, प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर उक्तवत सहित पाठ्यक्रम होंगे। विद्यमान अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण साधनों के साथ सभी को प्रशिक्षित कराने के लिए प्रबन्ध किया जायेगा।

छ. एटीआई और अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान ऐसे प्रशिक्षण के लिए सुदृढ/विकसित किए जाएंगे।

ज. राज्य योजना यह है कि विभिन्न विभागों में उसके सूचना प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के लिए वास्तविक सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ग के भाग के रूप में ई-गवर्नेंस/सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सर्वोच्चता के रूप में कृत्य कर सकेगी। यह विभाग अथवा जिलाधिकारी (यदि वह जिले स्तर का अधिकारी है) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भी सूचना देगा। यह अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को प्रदान करेंगे जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के समस्त मामलों को देखने के योग्य हो सके।

6- सुरक्षा:

क. सरकार स्मार्ट कार्ड और बायोमैट्रिक्स का प्रयोग करने के लिए बहुत से स्थानों पर बढ़ावा दे रही है, यथा बैंकिंग, फुटकर भुगतान, वाहन रजिस्ट्रीकरण, इंटरनेट भुगतान, नागरिक चिन्हांकन, राशनकार्ड, पेंशन, ड्राइविंग अनुज्ञा, स्वास्थ्य रिपोर्ट इत्यादि।

ख. सरकार डिजिटल लाकर, डिजिटल प्रमाणन के प्रयोग को बढ़ावा देगी और विद्यमान प्रमाणन प्राधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं और सामान्य प्रयोग के लिए वहन युक्त मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चिन्हांकन करेगी।

ग. उत्तराखण्ड की सरकार शून्य साफ्टवेयर पाईरेसी सरकार को बनाये जाने का आशय रखती है।

7- सूचना प्रौद्योगिकी अनुकूलन और आकर्षित ज्ञान उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक विकास में तेजी लाना:

क. राज्य की आर्थिक बढ़ोतरी स्वमूल्य व्यापार/औद्योगिक गतिविधि तथा प्राकृतिक स्रोतों की बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धता है। राज्य का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र से वर्तमान जीडीपी आती है जो कि राज्य को सेवा प्रदाता आर्थिकी बनाती है। जीडीपी के लिए मुख्यतया पर्यटन, कृषि, औद्यानिक, चिकित्सा/ हर्बल सम्पदा तथा जल विद्युत सम्मिलित है।

ख. सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्यान में निजी निवेशकर्ताओं से उन्नयन करना चाहती है और पीपीपी रीति के अधीन निजी निवेशकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्लस्टर की सुविधा और बढ़ाने का विकल्प रखती है। इन क्लस्टरों के लिए भूमि राजस्व अंशदायी योजना पर

छूट दरों पर उपलब्ध करायेगी।

इलेक्ट्रानिक पद्धति डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) नीति का कियान्वयन

8- **संरचनात्मक विकास:** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग जिसमें उद्योग संगठन के लोग सम्मिलित होंगे, के सदस्यों से एक समिति का गठन किया जायेगा जो संरचनात्मक पहल की प्रगति को देखेगी। सिडकुल के परामर्श से राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विनिर्माण क्लस्टरों के विकास के लिए समुचित स्थलों का चिन्हांकन करेगी। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सिडकुल के परामर्श से निजी उद्योगों को उनकी अपेक्षा और उपबंधों के लिए राज्य के क्षेत्र क और ख श्रेणी में समुचित ईएसडीएम स्थलों का चिन्हांकन करेगी।

9- **उन्नयन ईएसडीएम क्षेत्र को संस्थागत तंत्र :** सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक विशिष्ट ईएसडीएम नोडल एजेंसी गठित करेगी। अभिकरण में उद्योग और सरकार के मुख्य प्रतिनिधि निम्नलिखित कार्य करेंगे—

एक— मुख्य निवेशकर्ताओं के साथ संयोजन सहित विनिवेश उन्नयन और अनुश्रवण;

दो— उत्तराखण्ड ब्रान्ड उन्नयन के माध्यम से मुख्य भूमण्डलीय सहभागिता और देशों में परिचालन जिससे कि निवेशकर्ता (अमेरिका, यूरोप, जापान, ताईवान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश) और सहयोगकर्ता को समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से विज्ञापन देकर आमंत्रित किया जाना;

तीन— क्षेत्र को गहराई से समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समिति कार्य करेगी।

10- **ईएसडीएम नीति के अधीन उन्नयन प्रोत्साहन :** ईएसडीएम नीति के अधीन निम्नवत उन्नयन प्रोत्साहन का विवरण एतद्वारा उत्तराखण्ड की सरकार द्वारा जिससे ईएसडीएम क्षेत्र में राज्य भारत में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सके और ईएसडीएम में निवेश के लिए प्राथमिक रूप से स्थानों में राज्य का नाम हो, दिया जा रहा है—

क. वरीयता बाजार पहुंच (पीएमए) नीति

एक— उत्तराखण्ड की सरकार, भारत सरकार के पीएमई नीति के साथ संयोजित होकर स्थानीय मूल्यों के विस्तार में प्रक्रिया संयोजन पर आधारित राजकीय अधिप्राप्ति के लिए राज्य में विनिर्मित इलेक्ट्रानिक स्थानीय उत्पाद को वरीयता देगी।

दो— घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रानिक उत्पाद वो उत्पाद है जो कि उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रीकृत और स्थापित कम्पनियों द्वारा विनिर्मित हो और विनिर्माण में सम्बद्ध हो और इसमें संविदा विनिर्माण सम्मिलित है किन्तु व्यापार सम्मिलित नहीं है।

ख. **ईएसडीएम क्षेत्र में अविष्कार और आर तथा डी के लिए ईको पद्धति का सृजन:** उत्तराखण्ड दो ईएसडीएम अविष्कार और आर तथा डी केन्द्र स्थापित करेगी जो कि उपक्रमों और कम्पनियों को जो मूल कियाकलाप के उनके उत्पाद की संकल्पना और कियान्वयन को चाहते हैं, पूर्णरूप से संरचना उपलब्ध कराये। इन केन्द्रों से यंत्रों की डिजाइन की यथा वीएलएसआई डिजाइन यंत्र, मूल भूत विकास सुविधाएं, परीक्षण सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं और अपेक्षित मानव शक्ति तथा घटक भण्डार के साथ अनुपालना और प्रमाणन प्रयोगशालाओं की अपेक्षा होगी। ऐसा प्रथम

केन्द्र गोविन्द बल्लभ पन्त, प्रौद्योगिक संस्थान, पन्त नगर के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पर की जायेगी और तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में स्थापित की जायेगी। ऐसा सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की संस्तुति पर आधारित सचिवों की समिति द्वारा निश्चित किया जायेगा।

ग. इलेक्ट्रानिक उत्पाद कलस्टर (ईएमसी): उत्तराखण्ड ईएसडीएम क्षेत्र में विनिवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय संरचना आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। राज्य ऐसे संरचना के विकास में जहां कहीं व्यावहारिक रूप से ठीक हों, पीपीपी रीति में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ायेगा। राज्य सरकार वर्ष 2025 तक राज्य में ईएमसी तीन के विकास को सहयोग करेगी। काशीपुर में ईएमसी के लिए प्रस्तावित स्थल इनमें से एक है और अन्य दो स्थलों को भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सिडकुल के परामर्श से चिन्हांकित किया जायेगा। ईएमसी में संरचनात्मक विकास के लिए उत्तराखण्ड की सरकार सहयोग करेगी जो कि कुल संरचनात्मक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

घ. उत्तराखण्ड ब्राण्ड अधिष्ठापन: सरकार भू-मण्डलीय निवेशक लोगों के लिए किसी आकर्षक ईएसडीएम केन्द्र पर उत्तराखण्ड के बाजार उपलब्ध कराये जायेंगे और ईएसडीएम के लिए उत्तराखण्ड ब्राण्ड को कठोरता से निर्मित किया जायेगा। राज्य, राज्य में सक्रिय निवेशकर्ताओं को सम्पूर्ण विश्व से उच्चतम ईएसडीएम कम्पनियों को सहभागिता के लिए आमंत्रित करेगा।

ड. शोध उन्नयन: सरकार पुरस्कार दिये जाने के माध्यम से ईएसडीएम क्षेत्र में शोध का उन्नयन करेगी। ईएसडीएम क्षेत्र में अच्छे आविष्कार को उद्योग और सुप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों से गठित संवीक्षा समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

च. ईएसडीएम में कौशल विकास:

एक— विश्व में कौशल पूंजी के रूप में भारतीय आरोहण के कम में ग्रामीण और अर्द्धशहरी युवाओं को विशिष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक कौशल विकास युवा को चलाना आवश्यक है।

दो— चरणबद्ध ज्ञान-अपेक्षा के कम में वार्षिक क्षमता के साथ उत्तराखण्ड में नये आईटीआई और डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना-नये संस्थान उद्योग कलस्टर, ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के निकट की सीमा से लगे हुए स्थानों पर होंगे।

तीन— उत्तराखण्ड राज्य रोजगार मिशन के 12वीं पंचवर्षीय योजना को ईएसडीएम क्षेत्र के एक लाख प्रतिष्ठित छात्रों का लक्ष्य।

चार— सभी-महानुपूर्व-संस्थानों में ईएसडीएम से सम्बंधित अनुसंधान में प्रोत्साहन।

पांच— कम्पनियों और विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त आर और डी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।

छ— राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अभिकरण के अधीन स्थापित किए गये टेलीकॉम कौशल परिषद् के साथ उत्तराखण्ड सरकार कार्य करेगी। उपरोक्त परिषद् द्वारा देशभर में टेलीकॉम क्षेत्र में आगामी 6 वर्षों में 5 मिलियन लोगों से अधिक को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

सात— राज्य सरकार राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और लाभ प्रदत्त योजना से लाभ दिलाये जाने के लिए अग्रेतर प्रयासों को लगातार बनाये रखेगा जिसका विषय पर भारत सरकार की ईएसडीएम नीति के अनुसार युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिये जाने का उद्देश्य है। उत्तराखण्ड की

सरकार ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास पर तत्कालिक डाइट योजना से कौशल विकास के लिए केन्द्रीयक स्वीकृत योजनाओं के भाग में तत्परता से कदम उठायेगी।

छ-प्रोत्साहन और सहायिकी का उच्च प्रदर्शन

एक-पेटेंट और आईपीआर के लिए प्रोत्साहन उच्चस्तरीय ईएसडीएम विनिर्माण ज्ञान शक्ति को सृजित करने की अपेक्षा करती है, जिसके लिए भारत और उसके साथ ही साथ बाहर भी पेटेंट के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है यह ऐसी गतिविधि है कि जिसे बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिससे कि उत्तराखण्ड आईपीआर और ज्ञान आर्थिकी में नेतृत्व प्रदान कर सके जिससे वाणिज्यिक सफलता प्राप्त हो सके। वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड ईएसडीएम कम्पनियों द्वारा ईएसडीएम में 2000 घरेलू और एक हजार अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रस्तुत किए जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत तक (जिसमें प्रस्तुतिकरण शुल्क, विधिक शुल्क, सर्च शुल्क, रख-रखाव शुल्क सम्मिलित है), घरेलू को पेटेंट करने के लिए अधिकतम ₹ 5 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय को पेटेंट करने के लिए ₹ 10 लाख की प्रतिपूर्ति करेगी। यह प्रतिपूर्ति पेटेंट के प्रस्तुत करने के पश्चात् 75 प्रतिशत देय होगी और अवशेष 25 प्रतिशत पेटेंट स्वीकृत होने के पश्चात् दी जायेगी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली पेटेंट प्रस्तुतिकरण प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी विद्यमान योजना के अतिरिक्त होगी।

ग्रामीण बीपीओ/केपीओ उद्योग

11-ग्रामीण बीपीओ/केपीओ निम्नवत् कारणों से अतिमहत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है-

- क. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि स्थानीय रोजगार के विकल्प का सृजन;
- ख. नौकरियाँ वहाँ होती हैं, जहाँ लोग होते हैं, के स्थान पर लोग जहाँ जायें, वहाँ नौकरियाँ हों-सामाजिक ताने-बाने को बनाये रखना, न्यून प्रवर्जन और शहरी दबाव;
- ग. घरों की आय में बढ़ोतरी, जो कि क्रय शक्ति को बढ़ाती है और ट्रिकिल डाउन प्रभाव के कारण, सृजन, विशिष्ट स्थानीय आर्थिक विकास, सहायक भौगोलिक स्थिति के अनुसार आय बढ़ाने में मदद;
- घ. ज्ञान कार्य बल के लिए नौकरियों की पहुँच सृजित करने के द्वारा लिंग अनुपात पर उच्चतर जोर दिया जाना, जिससे नौकरियों के लिए साधारणतया (युवतियों) बाहर न जाना;
- ङ. प्रत्येक वैयक्तिक प्रत्यक्ष रोजगार के लिए न्यूनतम 3-4 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार ऐसी-ईकाइयों-को-उपलब्ध कराने के लिए सहयोग और सामर्थता;
- च. मुख्य धारा में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को डिजीटल से जोड़े जाने के लिए मदद करना, आईसीटी के उच्चतर जागरूकता के उन्नयन सेवा आधारित ज्ञान में सहभागिता और सूचना तथा ज्ञान का वृहत्तर उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य चुनौतियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहयोग इत्यादि) में मदद करना;
- छ. बीपीओ सेवाओं में (शहरी क्षेत्रों में प्रभावी कार्ट नेतृत्व) भू-मण्डलीय नेतृत्व स्तर बनाये रखने के लिए भारत की मदद करना;

- ज. राज्य सरकार स्थानीय बीपीओ/केपीओ उद्योगों सरकार बीपीओ/केपीओ व्यापार (जैसे और जहाँ वह आये) का 25 प्रतिशत आरक्षित रखेगी। प्रतियोगी नीलामी पर एल 1 आधार के मूल्य पर सरकारी व्यापार (जैसे और जहाँ वह आये) के 25 प्रतिशत राज्य बीपीओ/केपीओ उद्योगों को दिए जायेंगे।

डाटा केन्द्र तथा डाटा केन्द्र पार्क

12-सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटलइजेशन के बढ़ते हुए प्रयोग के साथ डाटा संग्रहण की माँग बढ़ना स्वाभाविक है। यह डाटा केन्द्रों हेतु माँग सृजित करेगा जिससे प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में 24 डिग्री भीतर के किसी तापमान पर संचालन अपेक्षित होगा। उत्तराखण्ड अपने वातावरण पर विशेष रूप से पर्वतीय और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण समुचित संयोजिकता के लिए दोनों भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी संयोजिता में सहयोग करेगा, जिससे एक आदर्श स्थान पर डाटा केन्द्र स्थापित हो सके।

अध्याय -3 - प्रोत्साहन

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति (एनईपी) 2012 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन

1- एम-एसआईपीएस के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन: इस योजना पर आधारित इलेक्ट्रानिक उत्पादन विनिर्माण इकाईयां एसईजेड आधारित इकाईयों हेतु पूंजीगत खर्च के 20 प्रतिशत और गैर एसईजेड आधारित इकाईयों के लिए विनिवेश उपस्करों पर एक्साइज/सीबीडी के कुल पूंजीगत खर्च की प्रतिपूर्ति 25 प्रतिशत के लिए दिये जाने वाला प्रोत्साहन इलेक्ट्रानिक उत्पाद विनिर्माण इकाई को इस योजना के अधीन आधारित होगा।

2- ग्रीन फिल्ड और ब्राउन फिल्ड ईएमसी के लिए वित्तीय सहायता:

क. भूमि के प्रत्येक 100 एकड़ के लिए ग्रीन फिल्ड ईएमसी हेतु वित्तीय सहायता परियोजना मूल्य के 50 प्रतिशत तक अधिकतम 50 करोड़ आईएनआर तक सीमित होगी,

ख. ब्राउन फिल्ड ईएमसी के विस्तार/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता परियोजना मूल्य के 75 प्रतिशत तक जो कि 50 करोड़ आईएनआर तक सीमित होगी, दी जायेगी।

3- एमएसएमई द्वारा इलेक्ट्रानिक विनिर्माण क्लस्टर का विकास

क. ईएमसीएस अथवा ग्रीन फिल्ड या ब्राउन फिल्ड हेतु परीक्षण के व्यय की प्रतिपूर्ति- 2.50 लाख आईएनआर/ क्लस्टर,

ख. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परियोजना मूल्य की स्वीकृति धनराशि का 75 प्रतिशत साफ्ट विनिवेश हेतु हुए व्यय की प्रतिपूर्ति 2.5 लाख आईएनआर/ क्लस्टर तक सीमित होगी,

ग. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति- 5 लाख आईएनआर/ क्लस्टर।

4- अधिमान्य बाजार पहुंच: घरेलू विनिर्माण इलेक्ट्रानिक उत्पाद हेतु सरकारी अधिप्राप्ति में प्राथमिक बाजार पहुंच पर भारत सरकार की नीति उत्तराखण्ड सरकार के सभी विभागों पर क्रियान्वित होगी। उत्तराखण्ड आधारित विनिर्माण को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जायेगी।

5- प्राथमिक बाजार पहुंच

क. घरेलू और बाहरी किसी प्रयोगशाला से पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए परीक्षण अधिभार की प्रतिपूर्ति एसटीक्यूसी प्रयोगशाला द्वारा अधिरोपित परीक्षण अधिभार की लागू दरों के अनुसार एसटीक्यूसी प्रयोगशाला पर पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए हुए परीक्षण अधिभार के अध्यधीन होगी। योजना के अधीन अधिकतम प्रतिपूर्ति आईएनआर 75000 तक सीमित होगी।

ख. वार्षिक प्रत्येक मॉडल (घरेलू/बाहरी) के किसी संस्था प्रमाणन को भुगतान की जाने वाली वार्षिक सत्यापन शुल्क के साथ 25 प्रतिशत अधिभार की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित के अध्यधीन होगी-

एक- एक मॉडल के लिए आईएनआर 50000 तक

दो- योजना के अधीन केवल एक बार पात्र प्रत्येक मॉडल तथा दो प्रमाणन तक।

6- एमएसएमई के लिए भारतीय मानक के साथ अनुपालन से सम्बंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति:

क. एसटीक्यूसी प्रयोगशाला द्वारा अधिरोपित परीक्षण के लागू दरों के अनुसार (सर्बिलाइन्स के दौरान

के साथ साथ प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के लिए) एसटीक्यूसी प्रयोगशाला पर पदार्थ परीक्षण को प्राप्त करने के लिए हुए परीक्षण अधिभार को वास्तविक परीक्षण अधिभार के अध्यक्षीन प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस योजना के अधीन अधिकतम प्रतिपूर्ति आईएनआर 75000 तक सीमित होगी।

ख. रजिस्ट्रीकरण के लिए बीआईएस द्वारा वास्तविक परीक्षण अधिभार की प्रतिपूर्ति अधिकतम आईएनआर 25000 होगी।

7- कौशल विकास

क. इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए युवाओं के दृष्टिगत विनिर्माण और सेवा संयोग कृत्यों के कार्यों में रोजगार बढ़ाना,

ख. इलेक्ट्रानिक क्षेत्र कौशल परिसर, टेलीकॉम क्षेत्र कौशल परिसर और एनआईआईएलआईटी द्वारा चिन्हांकित प्रशिक्षित सहायता के लिए प्रशिक्षण शुल्क के लिए 75 प्रतिशत उपलब्ध कराने की योजना,

ग. कुल सीटों की 40 प्रतिशत तक शतप्रतिशत शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए भी योजना उपलब्ध है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किया जा सके,

घ. अग्रेतर प्रति अभ्यर्थी रजिस्ट्रीकरण एवं प्रमाणन (केवल प्रथम अवसर के लिए भी मानक /प्रमाणन अभिकरणों को प्रतिपूर्ति की जायेगी)

ड. उत्तराखण्ड के लिए 15 हजार (तीन हजार प्रतिवर्ष का लक्ष्य इस योजना से लाभान्वित करने के लिए नियत किया गया है)

8- आर और डी को बढ़ावा और राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा

क. भारत सरकार ने पांच सालों की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित तीन हजार सुधारियों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ख. इलेक्ट्रानिक उद्योगों में प्राप्ति को मान्य करने, क्षेत्र में ब्यूरो के उद्देश्य और निवेश को बढ़ाने और क्षेत्र के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार 3.5 करोड़ से अधिक के बजट के साथ विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार संरचित किए हैं।

क्षेत्रों का विभाजन

9- उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की श्रेणियों को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम ब्यूरो नीति 2015 के अनुसार परिभाषित किया जा चुका है। जहां प्रोत्साहन/सहायिकी की मात्रा के प्रयोजनार्थ चार श्रेणियों में राज्य द्वारा निम्नवत विभक्त किया गया है -

श्रेणी	सम्मिलित क्षेत्र
श्रेणी क	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सम्पूर्ण जिला।
श्रेणी ख	<ul style="list-style-type: none"> पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोडा सम्पूर्ण जिला। जिला देहरादून के समस्त पहाड़ी विकास ब्लाक के अतिरिक्त विकासनगर, डोईवाला, सहस्रपुर और राजपुर।

	<ul style="list-style-type: none"> जिला नैनीताल के समस्त पहाड़ी ब्लाक हल्द्वानी एवं रामनगर के अतिरिक्त।
श्रेणी ग	<ul style="list-style-type: none"> जिला देहरादून के विकास ब्लाकों रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला जो समुद्र तल से 650 मीटर से अधिक क्षेत्रों में स्थित है। जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास ब्लाक।
श्रेणी घ	<ul style="list-style-type: none"> हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण जिला। जिला देहरादून और नैनीताल के शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ख' और श्रेणी 'ग' में सम्मिलित नहीं है)

टिप्पणी— उपरोक्त क्षेत्रों का वर्गीकरण आईसीटी और ई नीति 2016 के लिए समान रहेगी।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन

वित्तीय प्रोत्साहन

10— राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन नीचे दिया गया है। नये उद्योग, विद्यमान उद्योग और विस्तारित उद्योग (विद्यमान उद्योग जो क्षमता विस्तार कर रही हो) को यह प्रोत्साहन को लागू करने के लिए नीचे तालिका में भी दर्शाये गये हैं। यदि कोई विद्यमान कम्पनी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नहीं है और सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थापन या कोई विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी क्षेत्र में कोई नया कारोबार संस्थापित करना चाहता हो उसे इस नीति के अनुसार नये उद्योग के रूप में समझा जायेगा।

क.सं.	प्रस्तावित प्रोत्साहन	नया	विद्यमान	विस्तार
1	पूंजी सहायिकी (उपकरण, संयंत्र और मशीनरी)	✓	×	✓
2	बंदी उपस्कर सहायिकी (विद्युत उत्पादन पद्धति)	✓	×	✓
3	भूमि मूल्य	✓	×	✓
4	स्टाम्प ड्यूटी छूट	✓	✓	✓
5	कर (मूल्य वर्धित कर) सहायिकी	✓	×	✓
6	ऋण सहायिकी पर ब्याज	✓	×	×
7	विद्युत सहायिकी	✓	✓	✓
8	प्रवाह उपचार संयंत्र (ईटीपी)	✓	×	✓
9	पेटेंट फिलिंग सहायिकी	✓	✓	✓
10	प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग	✓	✓	✓
11	रोजगार सृजन	✓	✓	✓

12	संयोजिकता अधिभार पर राज्य बीपीओ/केपीओ के लिए प्रोत्साहन	✓	×	✓
13	राज्य सरकार हेतु प्रोत्साहन खरीद/निविदाएँ आईसीटी तथा ई (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में है)	✓	✓	✓
14	मोबाईल टावर की स्थापना	✓	×	×

टिप्पणी—प्रतिशत मेगा औद्योगिक नीति के अनुसार।

11—राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन का विवरण नीचे तालिका में सूचीबद्ध की गई है।

क्र० सं०	सहायिकी	श्रेणी क	श्रेणी-ख	श्रेणी-ग	श्रेणी-घ
1	पूँजी सहायिकी (उपकरण, संयंत्र और मशीनरी)	45 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 45 लाख तक)		35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख तक)	
2	बंदी उपकरण सहायिकी (विद्युत उत्पादन पद्धति)	सभी श्रेणियों के लिए 20 प्रतिशत (सोलर, हवा या हाईब्रिड पद्धति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायिकी प्रदान की जायेगी)			
3	भूमि लागत सहायिकी	50 प्रतिशत (परियोजना के आकार के निरपेक्ष)	बड़ी परियोजना (₹ 50-75 करोड़): 15 प्रतिशत मेगा परियोजना (₹ 75-200 करोड़): 25 प्रतिशत अल्ट्रा मेगा परियोजना (> 200 करोड़): 30 प्रतिशत		
4	स्टाम्प शुल्क में छूट	100 प्रतिशत			
5	मूल्यवर्धित कर-दर	पहले पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात् 90 प्रतिशत	पहले पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात् 60 प्रतिशत		
6	ऋण पर ब्याज सहायिकी	12 प्रतिशत (प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम ₹ 10 लाख)	8 प्रतिशत (प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम ₹ 6 लाख)		
7	विद्युत सहायिकी (विद्युत अधिभार पर)	पहले पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत और उसके पश्चात् 80 प्रतिशत	पहले दस वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और उसके पश्चात् शून्य		
8	प्रवाह उपचार-संयंत्र	₹ 50 लाख की किसी सीमा के अध्यधीन ईटीपी के मूल्य के			

	(ईटीपी)	50 प्रतिशत तक एक समय के लिए पूँजी सहायिकी			
9	पेटेंट फाइलिंग	घरेलू पेटेंट—₹ 5 लाख अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट—₹ 10 लाख (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में हैं)			
10	प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग	वर्षा जल संचय—मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2 लाख) अवशिष्ट जल पुनःचक्रण—मूल्य का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 5 लाख)			
11	रोजगार सृजन	3 वर्ष के लिए (अधिकतम)	2 वर्ष के लिए (अधिकतम)	1 वर्ष के लिए (अधिकतम)	शून्य
11क	टिप्पणी	कर्मचारियों की संख्या के अध्वधीन सीधे कर्मचारियों से विनिर्दिष्ट अधिकतम ₹ 15000 हजार का अधिकतम वेतन आहरित करने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए ₹ 700 प्रतिमाह और महिला/ईडब्लूएस/एससी/एसटी के लिए ₹ 1000 प्रतिमाह			
12	संयोजिकता अधिभार पर राज्य बीपीओ/केपीओ के लिए प्रोत्साहन	पहले 3 वर्ष के लिए 50 प्रतिशत	पहले 2 वर्ष के लिए 30 प्रतिशत	शून्य	शून्य
13	राज्य के लिए प्रोत्साहन—आईसीटी और ई प्रौक्चौरमेंट/टेंडर्स (केवल ऐसी कम्पनियों के लिए जिनके मुख्यालय उत्तराखण्ड में हैं)	10 प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता			
14	मोबाईल टावर का संस्थापन	श्रेणी क: सरकारी प्रभार पर 100 प्रतिशत छूट. श्रेणी ख: सरकारी प्रभार पर 50 प्रतिशत छूट			

टिप्पणी—इकाई कर के वास्तविक मामले पर उसके समायोजन के आधार के अध्वधीन त्रैमास के अंत पर जमा किए जाने वाले कुल मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति और प्रथम त्रैमास के लिए कर जमा किया जा सकता है।

गैर वित्तीय प्रोत्साहन

12. राज्य सरकार राज्य में निवेशकों के लिए मित्रवत् व्यवहार सृजित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि—

- क. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तथा ईएसडीएम उद्योग के लिए भूमि का आवंटन प्राथमिकता से किया जाय,
- ख. राज्य में प्रत्येक जिले के लिए नोडल अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई जिला प्रबंधक/अन्य कोई अधिकारी को नामित/नियुक्त किया जाय,
- ग. सूचना प्रौद्योगिकी और ईएसडीएम उद्योगों को नियमित/बाधा मुक्त विद्युत आपूर्ति की जाय,
- घ. 24×7 बाधा मुक्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हरित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र दोनों को अतिरिक्त आपूर्ति दिये जाने की बाध्यता की जाय,
- ङ. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी और ईएसडीएम के लिए ऋण दिये जाने पर विचार किया जाय,
- च. सूचना प्रौद्योगिकी और ईएसडीएम उद्योगों के स्थान पर विद्यालय, आवासीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन और उससे सम्बन्धित सुविधाएँ की उच्च स्तरीय सामाजिक संरचना के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाय,
- छ. विभिन्न सरकारी विभागों से सरलता से पत्रावलियों का व्यवहरण और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्रशासनिक पद्धति उपलब्ध करायी जाय,
- ज. राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों और नियमावलियों से निरीक्षण/प्रमाणन से ईएसडीएम इकाईयों को छूट दी जाय।

बुनियादी सुविधाओं का समर्थन

13. राज्य ऐसी उच्च स्तरीय तकनीकी उद्योगों को लाभ के लिए आकर्षित करने का प्रयास करेगी—

- क. उद्योग की ताकत शांत और उचित वातावरण है। राज्य यह प्रयास करेगी कि इन उच्च स्तरीय तकनीकी उद्योगों को लाभ के लिए उसकी ताकत को, शांत और उचित वातावरण, शुद्ध जल, प्रतियोगी परिसम्पत्तियों का मूल्य, योग्य मानव संसाधन, उच्च स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य, सक्रिय प्रशासन और वायु, पेड़, सड़क और संचार संयोजकता के सुधार के लिए संरचना का विकास करना है,
- ख. उत्तराखण्ड राष्ट्रीय राजधानी से वायु, रेल और रोड परिवहन से जुड़ा हुआ है और दो गतिमान हवाई अड्डे पंतनगर और देहरादून में, 9 बड़े रेलवे स्टेशन और 20 बड़े बस स्टेशन उपलब्ध है,
- ग. उत्तराखण्ड में समेकित औद्योगिक क्षेत्र, आई0टी0 पार्क और हरिद्वार, पंतनगर, देहरादून इत्यादि उत्तराखण्ड के क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों में केन्द्र उपलब्ध है। देहरादून में विद्यमान आई0टी0 पार्क के अतिरिक्त राज्य सरकार रामनगर/पंतनगर में अतिरिक्त आई0टी0 पार्क की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी बड़े शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी हब और ईएसडीएम हब स्थापित करने का भी प्रस्ताव है,
- घ. सरकार सुनियोजित दृष्टिकोण से मात्रात्मक निवेशकों की शीघ्रता से पहचान करेगी और उसके कारोबार के विशिष्ट संदर्भ में उत्तराखण्ड के मूल्य को प्रस्तुत करेगी,
- ङ. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और ईएसडीएम में स्वयं के विकास के लिए आवश्यक संरचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखण्ड को समग्र उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी,
- च. सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि नये कारोबार को स्थापित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी कार्यवाहियों को सम्पादित करे,
- छ. सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सहभागिताओं के साथ कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करेगी।

अध्याय-4- अनुश्रवण और निष्पादन

1- यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि किसी नीति का सफल होना पूर्ण रूप से उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। यद्यपि यह देखा गया है कि सरकारी अधिष्ठानों में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस नीति के समग्र क्रियान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु समयबद्धता कर ली जाय। इन लक्ष्यों और मुख्य बिन्दुओं पर नियमित आधार पर पुनर्विलोकन किए जाने की आवश्यकता होगी। इस नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है-

क. उत्तराखण्ड राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सभी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

ख. आई टी विभाग, विभागों में ई गवर्नेन्स और विभागों के लिए आईसीटी रोड मैप के सृजन के लिए त्वरित चिन्हांकन को विभागों की बेंच मार्किंग करेगा। विभाग का सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ रोड मैप का क्रियान्वयन करेगा।

ग. विभिन्न ई-गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन करेगी जो कि नोडल एजेंसी के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र साफ्टवेयर विकासकर्ताओं/वेंडर्स/पद्धति समेकन सरकार के विभिन्न विभाग निकटता से कार्य करेंगे।

घ. ई-गवर्नेन्स परियोजना के प्रारम्भ करने के पश्चात् विभागीय मुखिया ज्ञान और संस्तुतियों पर पूर्ण रूपेण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ङ. किसी प्रारम्भ की स्वीकारिता का स्तर तक पहुंचने के लिए सामयिक पर्यवेक्षण किया जायेगा। रणनीतिक विकल्प और क्रियान्वयन में पाठ्यक्रम संशोधनों के लिए सजग रहने की आवश्यकता होगी।

च. सेवा प्रदान करने वाले नये प्ररूपों के सम्बंध में मूल्य बचत का परीक्षण तथा आखरी उपभोक्ता को मिलने वाली ऐसी बचत के बारे में सरकार परीक्षण करेगी।

छ. ऑनलाईन व्यवहरण के लिए सामुहिक मीडिया, प्रसार और विशेष प्रोत्साहन सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाया देने के लिए सरकार वास्तविक कार्य करेगी।

परिशिष्ट क

आईटी उद्योग/विस्तार/आईटी की परिभाषा सहित उद्योगों की श्रेणियां

1. कम्प्यूटर डिवाइस सहित:

क. डेस्कटॉप

ख. पर्सनल कम्प्यूटर

ग. सर्वर

घ. वर्क स्टेशन

ड. नोड्स

च. टर्मिनल्स

छ. नेटवर्क पीसी

ज. होम पीसी

झ. लेपटॉप कम्प्यूटर,

ञ. नोट बुक कम्प्यूटर,

ट. पाल्म टॉप कम्प्यूटर/पीडीए

2. नेटवर्क कंट्रोलर कार्ड्स/ मेमोरिज सहित:

क. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,

ख. एडाप्टर— एथरनेट/पीसीआई/ईआईएसए/काम्बो/पीसीएमआईसीए,

ग. एसआईएमएमएस— मेमोरी,

घ. डीआईएमएमएस—मेमोरी,

ड. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,

च. कंट्रोलर=एससीएसआई/अरे,

छ. प्रोसेसर—प्रोसेसर/प्रोसेसर पॉवर माड्यूल/अपग्रेड।

3. स्टोरेज यूनिट सहित:

क. हार्ड डिस्क ड्राइव्स/हार्ड ड्राइव्स,

ख. रेड ड्राइव्स तथा उनके कंट्रोलर,

ग. सी.डी. रोम ड्राइव्स,

घ. टेप ड्राइव्स—डीएलटी ड्राइव्स/डीएटी,

ड. ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स,

च. अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाइसेज,

4. अन्य: की बोर्ड, मॉनीटर, माउस और मल्टी मीडिया किट्स।

5. प्रिंटर तथा आउटपुट डिवाइस सहित:

क. डॉट मैट्रिक,

ख. लेजरजेट,

ग. इंकजेट,

घ. डेस्कजेट,

ड. एलईडी प्रिंटर,

च. लाइन प्रिंटर,

छ. एलईडी टीवी,

ज. प्लोटर्स,

झ. पासबुक प्रिंटर

6. नेटवर्क प्रोडक्ट सहित:

क. राउटर्स

ख. स्वीच,

ग. कन्सेन्टक्टर्स,

घ. टर्नस रिसीवर्स,

7. साफ्टवेयर सहित:

क. एप्लीकेशन साफ्टवेयर,

ख. ऑपरेटिंग सिस्टम,

ग. मिडिलवेयर/ फर्मवेयर,

घ. एंटी-वाइरस साफ्टवेयर,

8. कम्प्यूटर सिस्टम हेतु पावर सप्लाय सहित:

क. स्वीच मोड पावर सप्लाय,

ख. यूनिटर्पटेड पावर सप्लायस,

9. नेटवर्किंग/केबिलिंग तथा सम्बंधित सहायक (आईटी औद्योगिक सम्बंधित)

क. फाइबर केबल,

ख. कॉपर केबल,

- ग. केबल,
- घ. कनेक्टरर्स, टर्मिनल ब्लाक्स,
- ड. जैक पैनल, पैथ कार्ड,
- च. माउंटिंग कोर्ड/वाइरिंग ब्लाक्स,
- छ. सरफेस माउण्ट बाक्सेज,

10. उपभोग्य सहित:

- क. सीडी रोम/ कम्पेक्ट डिस्क,
- ख. टेप्स डीएटी/डीएलटी,
- ग. रिबन्स,
- घ. टोनर्स,
- ड. इन्जेक्ट कार्टेज,
- च. आउटपुट डिवाइस हेतु इंक

11. इलेक्ट्रानिक अवयव:

- क. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/ पापुलेटेड पीसीबी,
- ख. प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/पीसीबी,
- ग. ट्रांजिस्टर्स,
- घ. इंटिग्रेटेड सर्किट्स/आईसीएस,
- ड. डायोड्स/थाईरिस्टर/एलईडी
- च. रेसिस्टर्स,
- छ. केपासिटर्स,
- ज. स्वीच/(आन/आफ,पुस बटन,राकर इत्यादि)
- झ. प्लग्स/सॉकिट्स/रिलेस,
- ञ. मेग्नेटिक हैड्स, प्रिंट हेड्स,
- ट. कनेक्टर्स,
- ठ. माइक्रोफोन/ स्पीकर,
- ड. फ्यूज,
- ढ. इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले,
- ण. माइक्रो मोटर्स,

त. ट्रांसफार्मर

थ. मेजर आईओटी कन्सीट्यून्ट लाइक सेंसर, टॉसडयूसर और एक्यूटेअर,

द. बायो मैट्रिक प्रणाली, आरएफआईडीएस इत्यादि,

ध. एलईडी लाइट

12. दूर संचार उपकरणों में -

क. टेलीफोन,

ख. विडियोफोन,

ग. फेसिमाईल मशीन/फैक्स कार्ड

घ. टेली प्रिंटर/टेलेक्स मशीन,

ड. पीएबी एक्स/ ईपीए बी एक्स/ आर ए एक्स/एमएएक्स-टेलीफोन एक्सचेंज,

च. मल्टीपलैक्सस/ न्यूकसेज,

छ. मोडेम,

ज. टेलीफोन उत्तरीत मशीन,

झ. टेली कॉन्फ्रेंसिंग स्वीचिंग एपाटस,

ञ. ऐंटीना और मास्ट

ट. बायरलेस डाटा कॉम उपकरण,

ठ. प्राप्तकर्ता उपकरण जैसे पेजक, मोबाइल/ सेलूलर फोन इत्यादि,

ड. वीसेट

ढ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण,

ण. वीडियो और डिजिटल सिग्नलिंग दोनों के लिए सेट टाप बाक्स सहित,

त. मोबाइल फोन और उसके सहायक।

13. उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक और उपकरण

14. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं

क. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं वाणिज्यिक प्रक्रिया तथा सेवाएं, उत्पाद/सेवाएं निम्नलिखित हैं-

एक-भारत से बाहर वितरित,

दो- संचार नेटवर्क से वितरित

तीन-या तो वाह्य संविदात्मक (वाह्य स्रोत) या उसी कम्पनी (वाह्य अवस्थित) के किसी ग्रामीण सहायक द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

ख. सेवाएं जिन्हें सम्मिलित नहीं किया जायेगा—

एक— ग्रामीण उत्पादन/विनिर्माण इकाई,

दो— कम्पनी के निर्मित कार्यालय या उसकी स्थानीय शाखाएं,

तीन— इंटरनेट पर वास्तविक व्यापार,

ग— निम्नलिखित सेवाएं जिनमें उपर्युक्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी—

एक— बैंक कार्यालय संचालन,

दो— कॉल केन्द्र/वीपीओ केन्द्र,

तीन— विकास विवरण या एनीमेशन

चार— डाटा प्रक्रिया,

पांच— अभियांत्रिकी और आरेखण

छ— भूगर्भीय सूचना पद्धति सेवाएं

सात— मानव संसाधन सेवाएं

आठ— बीमा दावा प्रक्रिया,

नौ— विधिक डाटा बेस,

दस— चिकित्सीय प्रतिलिपि,

ग्यारह— पेटेंट,

बारह— ग्रामीण अनुसंधान,

तेरह— राजस्व लेखा,

चौदह— सहयोगी केन्द्र, और

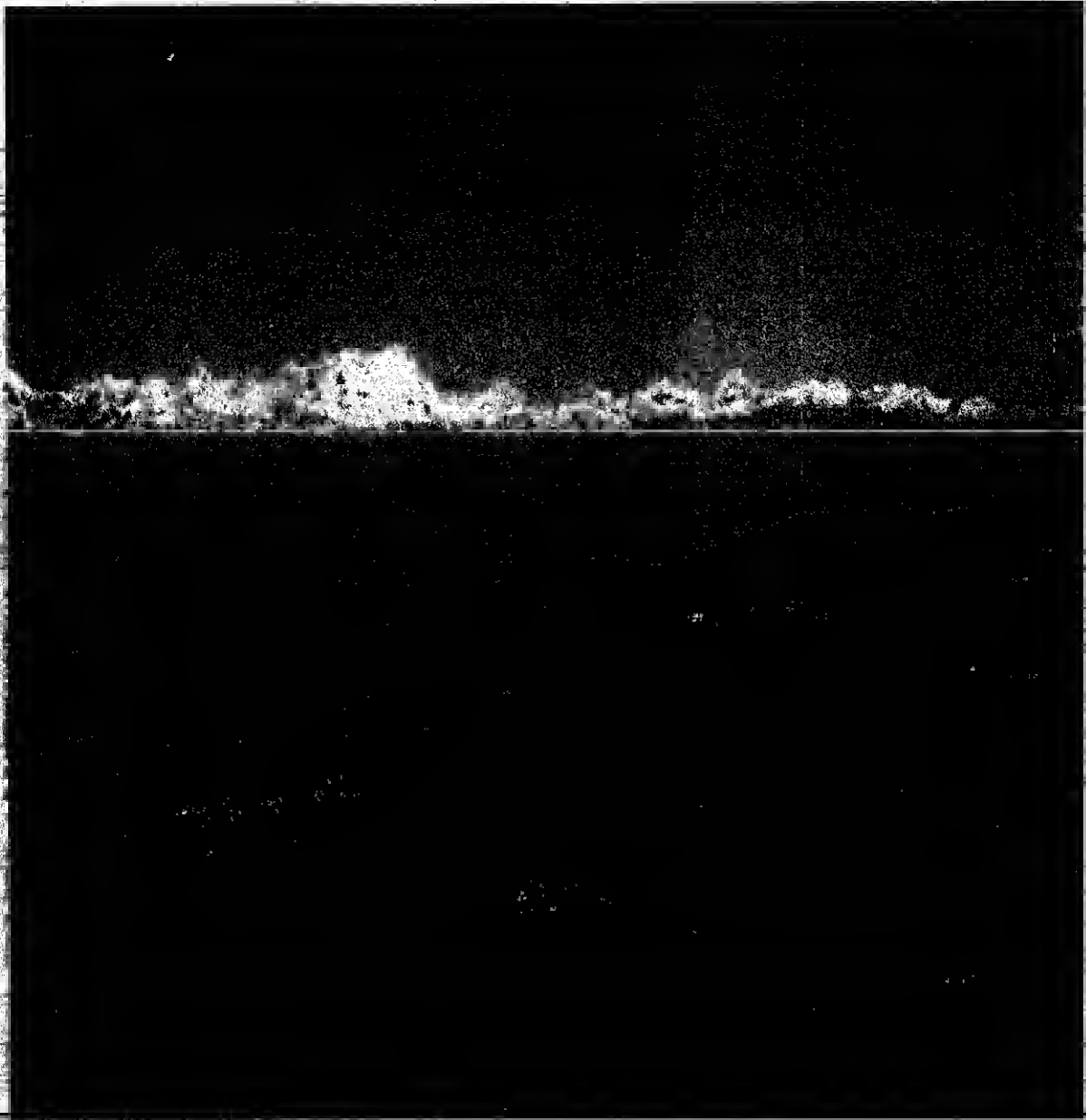
पन्द्रह— वेबसाइट सेवाएं।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

सचिव।

Information and Communication Technology & Electronics Policy Year, 2016-2025 (Uttarakhand State)



**Department of Information Technology
Government of Uttarakhand**

Table of Contents

CHAPTER 1- INTRODUCTION.....	150
Preamble.....	150-151
General.....	151
National Objectives.....	151-152
Vision.....	152
Goals.....	152-153
Mission.....	153
Objectives.....	153
CHAPTER 2-IMPLEMENTATION STRATEGY.....	154
Strategic Thrust.....	154
Implementation of Information and Communication Technology (ICT) Policy.....	154-158
Implementation of Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) Policy...	158-160
Rural BPO/KPO Industry.....	160
Data Centers and Data Center Parks.....	160
CHAPTER 3- INCENTIVES.....	161
Incentives Provided by Govt. of India Under the National Electronics Policy (NEP) 2012	161-162
Division of Regions.....	162
Incentives provided by Uttarakhand State.....	163
Fiscal Incentives.....	163-164
Non Fiscal Incentives.....	165
Infrastructure Support.....	165
CHAPTER 4 – MONITORING AND EXECUTION.....	166
Annexure A.....	167-169

CHAPTER 1 - INTRODUCTION

Preamble

1. **Information & Communication Technology and Electronics (ICT&E)** are **key drivers** of an increasingly knowledge based global economy. Given its current global position in the ICT&E sector, India is well positioned to enhance and leverage its capabilities towards this end. Industrialized and developing countries alike are formulating policies and programs to accelerate ICT and Electronics to reap the benefits of development and dissemination.
2. ICT&E is increasingly regarded as a "key" technology. It is regarded as generic, strategic and critical core area. All developing and developed countries have since recognized the importance of ICT&E and use a variety of policies and joint public-private programs to **increase ICT&E proliferation**. In developing countries also, it has been established that ICT&E has the potential to enhance competitiveness of key industries, modernize basic infrastructure and services, alleviate information poverty and reduce transaction costs throughout the economy. These countries use ICT&E in key areas like macro-economic planning and decision making, public administration, education, health-care, manufacturing, finance and banking, transportation, commerce, publishing, energy conservation and environmental management.
3. Major IT hubs in India like Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai, Pune and NCR which account for nearly 90% of the total ICT Industry in India are nearly saturated and face infrastructural challenges and human resource constraints for further expansion. This necessitates the absolute imperative for Indian ICT&E Industry to diversify into Tier II and Tier III cities of Uttarakhand. In line with the Global trends, it is imperative that State of Uttarakhand initiates timely and prompt measures with the aim delivering the benefits of ITC&E revolution to its residents.
4. The National Policy on ICT focuses on application of technology-enabled approaches to overcome monumental developmental challenges in education, health, skill development, financial inclusion, employment generation, governance etc. to greatly enhance efficiency across the board in the economy. The Uttarakhand State policy seeks to achieve the twin goals of **bringing the full power of ICT&E within the reach of the state** and **harnessing the capability and human resources of the state** to enable Uttarakhand to emerge as the Global/National Hub and destination for ICT, ITES and Electronic Manufacturing Services by 2025.
5. The focus of the ICT&E policy is therefore on deployment of ICT in all sectors of the economy, on providing IT solutions and to encourage private partners to set up electronics manufacturing units in the State. This Policy aims at attaining these objectives through coordinated action on the part of various key stakeholders within the State.
6. In addition to ICT proliferation, there is a need to set up and **enhance the electronics manufacturing units within the State** under the umbrella of "**Make in India**" initiative of the GoI. This would reduce the cost of various components that are currently being procured ex-import. Electronics Hardware Industry consists of electronic systems design and manufacturing which comprises of semiconductor design, high-tech manufacturing, electronic components and electronic system design for consumer electronic products, telecom products & equipment, IT systems and hardware. Electronics industry reported at USD 1.75 Trillion is the largest and fastest growing manufacturing industry in the world. It is expected to reach USD 2.4 Trillion by 2020.

7. **Key Stake Holders:** The key Stake holders in the State are not only IT Dept. (to include ITDA & SeMT) but also includes all Departments of the State including Police Department, Industry representatives from different associations, all Institutes/Universities under Higher Education and Technical Education Department and citizens of the State.
8. As per MSME Policy of the State, the State has been divided into four regions as covered in Chapter 3 and the incentives proposed there in are with the primary aim of boosting expansion of ICT&E infrastructure in remote areas.

General

9. The State of Uttarakhand was formed on the 9th November 2000 when it was carved out of Northern Uttar Pradesh. Largely a hilly State at the foothills of the Himalayan mountain ranges, its population currently stands around 1.08 Crores in a geographical spread of 53,483 Sq. Km of which approx. 88% is hilly terrain. The State is rich in natural resources especially water and forests with many glaciers, rivers, forests and mountain peaks. It's truly God's Land (Dev Bhoomi).
10. The Government of Uttarakhand proposes to harness the full power of ICT&E for *improving the quality of life* of its citizens, bring in *accelerated social and economic development*, ensure *transparency in the Government* decisions, *accelerate the IT adoption* amongst various user segments – all leading to an ideal e-society model through efficient, service oriented, cost-effective, information networked, eco-conscious, and with year-on-year growth approach. In addition, Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) is the fastest growing segment. As per the National Electronics Policy-2012 (NEP-2012), ESDM is expected to grow to US\$ 400 Billion by the year 2020 and will generate a total employment of over 28 million.
11. The purpose of this document is to provide a policy framework for effective infusion and management of ICT&E for achieving a genuine progress of the State in all its aspects. This policy document will become an extended document to the Uttarakhand MSME policy 2015 and Uttarakhand Mega Industries & Investment policy 2015.
12. This Policy document would be reviewed after every three years to monitor the progress made within the State and necessary amendments would be issued thereafter. It is further added that NeGD compiles on a Quarterly basis the progress made by the State for various e-Governance related projects to prepare the National e-readiness Report wherein the various aspects of ICT readiness are indexed, ranked and compared across all States and UTs of India. All Departments are requested to adhere to the timelines issued by the IT Dept. for various ICT related aspects within their respective Depts.

National Objectives

13. It is imperative that the State ICT&E Policy is aligned with the National Policies on the subject. In view of this, the key objectives of the National Policies on "*Information Technology 2012 (NPIT 2012)*", "*Notional Policy on ESDM 2012*", "*Notional Electronics Policy 2012 (NEP-2012)*" and "*Notional Telecom Policy 2012 (NTP-2012)*" are included in this document and summarized below:
 - (a) To increase revenues of IT and ITES Industry from 100 Billion USD at present to 300 Billion USD by 2020 and expand exports from 69 Billion USD at present to 200 Billion USD by 2020.

- (b) To gain significant global market-share in emerging technologies and Services.
- (c) To promote innovation and R&D in cutting edge technologies.
- (d) To encourage adoption of ICTs in key economic and strategic sectors to improve their competitiveness and productivity.
- (e) To provide fiscal benefits to SMEs and Startups for adoption of IT in value creation
- (f) To create a pool of 10 million additional skilled manpower in ICT.
- (g) To make at least one individual in every household e-literate. The State of Uttarakhand would endeavor to make all residents e-literate by 2025.
- (h) To provide for mandatory delivery of and affordable access to all public services in electronic mode.
- (i) To enhance transparency, accountability, efficiency, reliability and decentralization in Government and in particular, in delivery of public services.
- (j) To leverage ICT for key Social Sector Initiatives like Education, Health, Rural Development and Financial Services to promote equity and quality.
- (k) To make India global hub for development of language technologies, to encourage and facilitate development of content accessible in all Indian languages and thereby help bridge the digital divide.
- (l) To enable access of content and ICT applications by differently-abled people to foster inclusive development.
- (m) To leverage ICT for expanding the workforce and enabling life-long learning.
- (n) To strengthen the Regulatory and Security Framework for ensuring a Secure and legally compliant Cyberspace ecosystem.
- (o) To adopt Open standards and promote open source and open technologies.
- (p) To create an eco-system for a globally competitive ESDM sector in the country to achieve a turnover of about USD 400 billion by 2020 involving investment of about USD 100 billion and employment to around 28 million people at various levels.
- (q) To build on the emerging chip design and embedded software industry to achieve global leadership in Very Large Scale Integration (VLSI), chip design and other frontier technical areas and to achieve a turnover of USD 55 billion by 2020.
- (r) To build a strong supply chain of raw materials, parts and electronic components to raise the indigenous availability of these inputs from the present 20-25 per cent to over 60% by 2020.
- (s) To increase the export in ESDM sector from USD 5.5 billion to USD 80 billion by 2020.
- (t) To significantly enhance the availability of skilled manpower in the ESDM sector. Special focus on augmenting postgraduate education and to produce about 2,500 PhDs annually by 2020.

Vision

1. *"To use ICT&E as a vehicle for economic development of State of Uttarakhand with all round inclusive growth to create a vibrant society with high quality of life."*

Goals

15. Make the State of Uttarakhand **fully digitized** and **networked society** where information flow and access across all sections of the society would be enabled through effective ICT infrastructure that would **propel the economic growth** of the State.
16. **Employment Generation.** Given the fairly high literacy rate of 78.82% (higher than the national average), the Government aims to reduce unemployment by encouraging ICT, ITES and electronics manufacturing to establish their enterprises in Uttarakhand.

17. To make **electronics as growth engine** for the state and to establish Uttarakhand as the most preferred destination for investment in the Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) industry.

Mission

18. The mission of this Policy is to :

- To position State of Uttarakhand as an attractive **ICT&E investment destination** in India.
- To leverage **ICT & E as an engine of growth** for Uttarakhand.
- To transform physical communities into **connected communities** that can help to realize **sustainable economic growth and enhance the quality of life**.

Objectives

- Promoting Uttarakhand as an **attractive investment destination** for ICT&E companies by providing congenial, industry-friendly and proactive working environment.
- Promote prominent cities/towns in the State as emerging ICT&E destinations by providing **assistance in setting up** state of the art infrastructure in the state. this would be achieved by providing Single Window Assistance within the State.
- To create world class ICT infrastructure as a platform to provide **seamless connectivity** for business and users, easy to use public and private services in a vibrant ecosystem consisting of ICT operators, Service Providers, Government, Regulators and end users. The State Govt. plans to setup Electronic Manufacturing Clusters (EMCs) under PPP Model.
- To upgrade and **develop manpower skills** required for the ICT&E industry and to accelerate the use of ICT in schools, colleges and other educational institutions with a view to providing skills and knowledge to the youth so as to render them fit for employment in this industry. The State Govt. plans to encourage academic institutions, ITIs/Polytechnic Institutes, private players in imparting Low and High level Skills to students and un-skilled/semi-skilled personnel of the State with the overall aim of training and absorption of at least 1000 such personnel per year by MNCs and Local Industry.
- Encourage the use of **ICT in the Government** not only as a tool for management and decision support systems but also to re-engineer the processes of the government to provide a more efficient, transparent, accountable and responsive government to its citizens. The Govt. of Uttarakhand would take a lead in implementing IT in all its functioning.
- To upgrade the quality of life of citizens of the State by facilitating **easy access to consumer applications** of ICT.
- To use ICT&E as GDP driver by promoting ICT&E industry in the State, developing the State as an attractive ICT&E destination with a view to **generating employment for youth** in this sector thereby raising their earning capacity and simultaneously realizing the export as well as domestic revenue potential in this sector.
- To promote **indigenous manufacturing of electronics** products by creating a favourable investor friendly atmosphere in the entire value chain of ESDM.
- To promote the development of a **vibrant eco-system of R&D**, design and engineering and innovation in Electronics in the state with the State Government to be playing a proactively important role in this.
- Target **direct and indirect employment generation for 8000-10000** state residents per year within the state.
- Ensure utilization of allotted vacancies under National Policy on Skill Development in ESDM Sector and **train 15000 personnel** till 2019. The number of personnel to be trained thereafter would depend on the enhancement/extension of this policy at the National level.

CHAPTER 2 – IMPLEMENTATION STRATEGY

Strategic Thrust

1. There are six strategic thrust areas – 3 pillars supported by 3 foundations. The three pillars include **Economic Transformatlan, People Empowerment & Engagement** and **Innovations**; which need to be supported by strong foundation which include **Infrastructure Develapment, Human Capital Development** and **bridging the digital divide**. All six thrust areas would will lead to the emergent of ICT&E as an engine for growth for Uttarakhand State; recognition of Uttarakhand as the most preferred ICT&E destination in India and result in enhancement of quality of life for the residents of the State. The State Govt. also plans to set up second IT and Education Hub besides the one existing IT Park at Dehradun. The Govt. of Uttarakhand also plans to set up Data Center Clusters in Hilly areas to leverage the cold weather conditions in the State. The second IT & Education Hub and Data Center Clusters are planned to be set up in next two years and shall be administered by IT Dept.
2. **Earmarking of IT Budget:** All State Departments would earmark certain percentage of their Annual Budget for creation and enhancement of IT Infrastructure.

Implementation of Information and Communication Technology (ICT) Policy

3. Good Governance through ICT

- (a) Recognizing the fact that good Governance is primarily the combined effect of People, Processes and Technology, the Government of Uttarakhand would strive to deploy 'state-of-art' technologies supported by optimized administrative processes, simplifying the interface of the citizens and businesses with the Government, and building adequate skills among people in the effective use of ICT. The state shall use information as a tool for empowerment of its citizens.
- (b) As such, one of the goal of the Government is to **caoperate, callabarate and integrate information across different departments in the State and the Centre** that would help in delivering prompt services to the citizens, businesses and other Government Departments, in a manner that simplifies Government processes and aggregates different Inter-related services amongst various Departments.
- (c) Government targets to provide most of the **citizen centric services through electronic made** by 2018. To achieve the same, state wide roll out of e-District and other Mission Mode Projects (MMPs) that are underway. Government targets to bring most of the citizen centric services transparently and efficiently through these projects from a single portal.
- (d) Government targets to **computerize all internal government process** by end of 2018. Government plans to go "Paper Less" by this time. ERP systems including HRMS, e-Office, e-File will be implemented in all Govt. Departments. **Digital signatures / eSignature** will be provided to all the officials for this purpose.
- (e) Use of **Digital Lackers** would be encouraged wherein the citizens can secure personnel documentation on secure media and share the same with various agencies when required rather than submission of photocopied documents. This process would start with all Govt. officials who would be encouraged to utilize this facility.
- (f) Through e-Governance, the State of Uttarakhand believes in **anytime, anyplace delivery of a government service** to its citizens. The choice must rest with the citizen and not with the government department. The State shall therefore use technologies to overcome the handicap imposed by its terrain to deliver such services through CSCs/Internet.

- (g) The State Govt. plans to adopt new generation technologies based on best industrial practices and guidelines issued by Central Govt. from time to time. The State Govt would inculcate **Cyber Discipline** within all the Depts. Of the Govt to reduce loss of valuable data.
- (h) Special emphasis will be laid to provide user interface in a form and manner that is easy and convenient for large sections of the society to interact with the technology interface. A choice of devices – PCs, telephones, digital TV, mobile devices, kiosks, Personal Digital Assistants etc. will be considered to **create and support an infrastructure** to facilitate pervasive online access, subject to device suitability to support transactions. The Government plans to provide impetus to following aspects:

- (i) Coordinate with Central Government agencies, banking / financial institutions and NGOs for funding of efficient access devices (for internet / broadband access) to the citizens.
- (ii) In order to ensure access for the citizens to the Government offices and relevant Information, the state is setting up **Common Service Centers (CSCs)** in all villages in line with the Common Services Centre Scheme proposed by the Department of Information Technology, Government of India. These CSCs shall serve as the common access point to the Government and its various offices.
- (iii) Government targets to implement **State Resident Data Hub (SRDH)** project to prepare a database of all the state residents, which can be used by all other applications as a central repository of beneficiaries under various schemes. This database will be linked with AADHAR for authentication and deduplication services. This data base will provide enormous help in avoiding leakages in government schemes and also act as decision support system in planning of various welfare schemes. However, confidentiality of personal data as per GOI guidelines vis-à-vis guidelines issued by Honorable Supreme Court Would be strictly adhered to. Initially following departments will be made **AADHAR ready** :

- Department of Social Welfare
- Department of Food and Civil Supplies
- Department of Rural Development
- Department of Urban Development
- Department of School Education
- Department of Higher Education
- Department of Technical Education
- Department of Health
- Department of Revenue
- Department of Employment

- (i) The IT department would work closely with other departments in the State to identify opportunities for improving the internal efficiencies of these departments with the aim of enhancing the speed of delivery of their services to the citizens.
- (j) Given the difficult mountain terrain for the hill districts, ICT can play a very important role for delivering quality education & healthcare services. ICT would also be used for strengthening disaster management systems.

4. Building an effective ICT Infrastructure

(a) Supporting National ICT Policies

- (i) Various initiatives under National e-Governance Plan (NeGP) of the Department of Information Technology, Government of India relating to **State Wide Area Network (SWAN), Common Service Centers (CSCs), State Data Centre (SDC)** etc. will be

implemented as per the directives of the Central Government. Additional Infrastructure needed beyond the central support will be provided for by the State Government.

- (ii) **SWAN: State Wide Area Network (UKSWAN)** is already in place connecting the State Head Quarters (SHQ) with all the 13 District Headquarters (DHQs) and DHQs to respective Block Headquarters (BHQ) / Tehsil Headquarters (THQ).
- (iii) **CSCs:** Government of India has formulated a National e-Governance Plan (NeGP) with the vision of providing all Government Services in an integrated manner at the doorstep of the citizen, at an affordable cost. One of the models for delivery of "**Web-enabled Anytime, anywhere access**" to information and services in rural India under the project Common Services Centers (CSCs), ICT enabled centers in the rural areas covering all the Districts will be created.
- (iv) **SDC:** It will provide consolidation of services, applications and infrastructure to render efficient electronic **delivery of G2G, G2C and G2B** services. It will provide storage where all Government departments' data, application servers, web servers, and mail servers can be resided. The State is coming up with state-of-the-art SDC at IT Bhawan located at IT Park, Dehradun.

(b) Technology - Architecture & Standards

- (i) In developing an e-Governance Architecture Framework, due recognition will be given to the role of the different players in the service creation and delivery, such as the Service Seekers, Government Service and other third-party service providers such as authentication and payment gateway services, network providers, Infrastructure Management services and will provide hassle free interface amongst these players to ensure smooth and efficient creation and delivery of services, ensuring **24 X 7 quality of services through effective Public - Private - Partnership models**.
- (ii) Based on the framework being adopted by the Centre, the State will follow and will mandate compliance to those **e-Governance Standards** relating to interoperability, Data and Metadata as recommended by the Department of Information Technology, Government of India as and when these Standards are released.
- (iii) The Government of Uttarakhand is technologically neutral but it is necessary for integration that any software is based on open standards and its integration standards are defined. Therefore, Government of Uttarakhand will work on transparent standards.
- (iv) The Government recognizes the need to be free of any technology / vendor domination and will therefore encourage multiple technologies and vendors to co-exist that would contribute to the improvement in the quality of services rendered by these vendor's / service providers. This would provide the necessary leeway for newer technologies to be brought in. This accelerates the private participation in the delivery of services for the citizens.

(c) Network / Communication Infrastructure

- (i) Creation of a connectivity backbone is the foundation on which the building blocks of e-Governance initiatives will be placed. A **State Wide Area Network (SWAN)** is already in place for connectivity across the state. The SWAN guidelines and support from the Centre will be utilized to fully reap the benefits of the communication infrastructure. The Government will encourage proliferation of other **Public and Private Networks** to increase the bandwidth availability and to bring price affordability through competition.
- (ii) State targets to provide connectivity to all the government departments of the state through **horizontal connectivity** scheme under SWAN.

- (iii) State targets to achieve connectivity till Gram Panchayat (GPs) level by end of 2017 through the implementation of **National Optical Fiber Network (NOFN)** project of Government of India. State pledge to support in speedy implementation of this project by providing timely approvals required for the scheme and whatever support required.
- (iv) To encourage tourism in the state, the State would provide free Wi-Fi Services at tourist/pilgrimage locations and DHQs in a phased manner.

(d) **Mobile Communication:** With the advancement of technology, quantum surge in data consumption, increasing tele-density and robust growth in the number of consumers with smart phones, the need to establish many more towers especially in the remote areas has become very necessary. Mobile towers in required numbers are essential for any mobile network and the absence of these is bound to result in gaps in the mobile coverage, leading to degradation of services, slow internet speeds and call drops. Large remote and hilly parts of Uttarakhand State are still uncovered by mobile connectivity thereby denying the basis services to the residents of these areas. In order to promote setting up of mobile towers in these areas, The State Govt. would provide incentives to Service providers. The State Govt. would also encourage Govt. Depts. To explore usage of Govt. Buildings/lands for installation of Mobile towers.

5. Developing Human skills

- (a) In the area of ICT, the State Government will address development skills that have the potential for increasing employment opportunities - **Building the capacity of citizens**, especially the youth, Government employees, teachers, industrial employees, rural communities including women, providing employment opportunities in information technology industry.
- (b) As part of the capacity building exercise, the Government of Uttarakhand aims at universal computer/digital literacy. Towards this end, Government of Uttarakhand is in the process of digitalization of all the schools and colleges of the state. Various other initiatives under **Rasht Riya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)** and **Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)** to increase computer/digital literacy are underway implementation. The state would leverage the existing ITIs, Polytechnic Institutes and link these to the nearest ICT&E industry.
- (c) The State would leverage existing Technical Institutes and private firms and carry out collaborative R&D efforts that could benefit the population.
- (d) Every passing student (From State Government Schools/Colleges) should possess adequate ICT skills. Keeping in trend with the fast paces ICT revolution, Schools and Colleges would be encouraged to incorporate these in their curriculum.
- (e) Capacity building within the Government will be taken up based on the guidelines of the **Department of Information Technology, Government of India under the National e-Governance Plan**. This will include a mix of **outsourcing and in-house competencies** for various skill levels such as Program Management, Business Process Reengineering, Change Management, Architecture designs, etc. Various Specialized Training in e-Governance (STeP) modules are being conducted and more are planned for the government officials of all the departments. Leadership Meet / Seminar for top level politicians and bureaucrats of the state is planned to bring awareness about ICT among them so that everyone is on the same page to achieve common goal.
- (f) Every new government official will be provided with **15 days mandatory training** on ICT in first year. These courses would include basic to medium level computer literacy modules. Refresher courses of 3 days will be imparted after every 2 years. Arrangements to train all existing officials with such training modules will be made.
- (g) ATIs and other government training institutions will be strengthened/developed for such

trainings.

- (h) Government plans to have **anbaard Virtual IT Cadre to assist various departments in their IT initiatives**. As part of IT cadre they will work on e-Governance / IT projects and act as "IT Champion". They will report to the department or DM (in case of district level officer) as well as have dotted line reporting to the IT department. These officials will be provided with intensive IT training so that they will be able to oversee the assigned IT projects.

6. Security

- (a) The Government will encourage use of **smart cards** and **biometrics** across many domains such as banking, retail payments, vehicle registration, internet payments, citizen identity, ration cards, pensions, driving licenses, health records etc.
- (b) Government will encourage use of **digital lockers**, **digital certificates** and will identify existing certifying authorities and service providers and strive to keep the prices affordable for common use.
- (c) The Government of Uttarakhand is intended to be a Zero Software Piracy Government.

7. Accelerating Industrial Growth through IT Adoption and Attracting Knowledge Industries

- (a) The economic growth of a State is driven by increased value-added business / industrial activity and the availability of a rich set of natural resources. A major portion of the State's GDP currently comes from the services sector, making the State a **service oriented economy**. The main contributors to GDP include Tourism, Agriculture, Horticulture, Medicinal / herbal wealth and Hydro energy.
- (b) Government is firm to **promote private investment in the IT industry** in the State. The State would facilitate and encourage adoption of IT clusters by private players under PPP model. The lands for these clusters would be provided at discounted rates on revenue sharing model.

Implementation of Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) Policy

8. **Infrastructure Development:** A committee comprising members from IT Department and industry including industry associations would oversee the progress of infrastructure initiatives. State IT Department in consultation with SIIDCUL would identify the suitable sites for development of manufacturing clusters. The State IT Dept. would also in consultation with SIIDCUL identify suitable EMC sites in A & B category regions of the State for its acquisition and provisioning to private industry.

9. **Institutional Mechanism to Promote ESDM Sector:** The State would constitute an ESDM specific nodal agency headed by Secretary, the Department of IT. The agency will have officials from industry and government with the following key responsibilities:

- (i) Investment promotion & monitoring including liaison with key potential investors.
- (ii) **Pramating Brand Uttarakhand** through participation in major global expos and conducting roadshows in countries that have potential investors (the US, Europe, Japan, Taiwan, Korea and other countries of South East Asia) and supported by print and digital media advertising.
- (iii) The committee should also have technical experts with in-depth understanding of the sector.

10. **Pramational Initiatives under the ESDM Policy:** Government of Uttarakhand hereby outlines the following promotional initiatives under the ESDM Policy, which will enable the State to be a

leading contributor in India's ESDM sector and make the State a preferred destination for investments in ESDM.

(a) Preferential Market Access (PMA) Policy

- (i) The Government of Uttarakhand would give preference to locally manufactured electronic products in the State for Government procurements based on the criteria linked to the extent of local value addition in line with the PMA of the GOI.
- (ii) Domestically manufactured Electronic products are those that are manufactured by companies registered and established in Uttarakhand and engaged in manufacturing, including contract manufacturers, but excluding traders.

(b) Creation of Eco-System for Innovation and R&D in ESDM Sector. Uttarakhand will set up *two ESDM Innovation & R&D Centers* that will provide complete infrastructure to entrepreneurs and companies who want to take their product concept and implement a working prototype. These centers would have requisite design tools such as VLSI design tools, prototype development facilities, testing facilities, characterization labs, compliance and certifications labs along with requisite manpower and component stocks. The first such center shall be housed at College of Technology, GBPUAT, Pant Nagar and subsequent center will be setup in other part of the state. This would be decided by a Committee of Secretaries based on the recommendation of Secretary IT.

(c) Electronics Manufacturing Clusters (EMC): Uttarakhand will promote the creation of high-class EMCs to provide world-class infrastructure facilities necessary to attract investment into the ESDM sector. The State will encourage participation of the private sector in a PPP mode, wherever practical, in developing such infrastructure. The State Government would support *development of 3 (three) EMCs in the State by 2025*. One of the proposed site for EMC is Kashipur, other two sites would be identified by the IT Dept. in consultation with SIIDCUL. Support of Government of Uttarakhand for infrastructure development in EMCs shall not exceed 10% of the total infrastructure cost.

(d) Establishing Uttarakhand Brand: The Government will market Uttarakhand as an attractive ESDM center for the global investor audience and build a strong "Brand Uttarakhand" for ESDM. The State shall engage with the top ESDM companies across the world to pro-actively invite investments in the state.

(e) Innovation Promotion: Government will promote innovation in the ESDM Sector through Awards by way of grants. The best innovations in the ESDM sector will be selected by the Screening Committee comprising of Industry and Academia representatives.

(f) Skill Development in ESDM

- (i) In order to enable India's ascent as the 'Skill Capital of the World', it is imperative to create a vehicle to vocationally skill Indian youth, with special focus on rural and semi-urban youth, so as to create inclusive growth.
- (ii) Establishment of new ITI/Diploma institutes in Uttarakhand with an annual intake capacity in line with the phase-wise talent requirement. — new institutions would come up in the close vicinity of the industry clusters, near rural and semi-urban areas.
- (iii) Addition of a target of 10000 trained students for ESDM sector to the 12th five-year plan targets of Uttarakhand state employment mission.
- (iv) Masters courses in ESDM related disciplines in all major institutes.
- (v) Encouraging joint R&D labs by companies and universities.
- (vi) The Government of Uttarakhand would work with the Telecom Sector Skill Council (TSSC) which has been established under the aegis of National Skill Development Corporation (NSDC) with a mandate to train 5 million people over the next 6 years in the telecom sector.
- (vii) The State Government would continue to put forward efforts in reaping benefits from the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme (STAR) which is aimed at

encouraging skill development of the Youth as per GoI ESDM Policy on the subject. Government of Uttarakhand would aggressively pursue to be part of centrally sanctioned schemes for skill development e.g. the current DeitY scheme on skill development in the ESDM sector.

(g) Post-performance incentives and subsidies

Incentives for Patents and IPR: High-value-added ESDM manufacturing requires creation of Intellectual Property (IPR) which needs to be protected in the form of Patents, both in India as well as abroad. This is an activity that needs to be actively encouraged so that Uttarakhand becomes a leader in IPR and knowledge economy, which in turn will result in significant commercial success. The target is to file 2000 domestic and 1000 international patents in ESDM by Uttarakhand ESDM Companies by 2025. The Government shall reimburse up to 50% of the actual costs (including filing fees, attorney fees, search fees, maintenance fees) with a maximum of INR 500,000 for filing a domestic patent and up to INR 1,000,000 for filing an international patent. This reimbursement shall be payable 75% after the patent is filed and the balance 25% after the patent has been granted. The patent filing Incentives provided by Government of Uttarakhand shall be in addition to any existing scheme of Govt. of India.

Rural BPO/KPO Industry

11. Rural BPO/KPO is one of the most important industry due to the following:

- (a) Create non-agricultural local employment option in rural areas
- (b) Jobs move to where people are, rather than people moving to where jobs are – retains social fabric, less migration & urbanization pressures.
- (c) Increased household income creates greater purchasing power and due to trickle-down effect, creates significant local economic development; helps bridge income divide geographically.
- (d) Greater thrust on gender diversity by creating access to jobs for latent work-force which usually will not migrate for jobs (young women).
- (e) Ancillary and support services to such units provide indirect employment to at least 3-4 more people, for every individual directly employed.
- (f) Helps create a digital-link to “connect” remote rural areas into mainstream: participation in knowledge based services promotes greater awareness of ICT and better usage of knowledge and information for other challenges in rural areas (education, health, agriculture support etc.)
- (g) Helps India to maintain global leadership position in BPO services (cost-leadership Impacted in urban areas).
- (h) The State Govt. would reserve 25% of government's BPO/KPO business (as and when it comes up) for local BPO/KPO industry. The State BPO/KPO Industry would be awarded 25% of the Government Business (as and when it comes up) at the price of 11 back to competitive bidding.

Data Centers and Data Center Parks

12. With the growing use of Information Technology and Digitization, the demand for data storage is increasing phenomenally. This is creating demand for data centers, which require operating at a temperature of around 24 degrees in a pollution free environment. Uttarakhand with its cool climate, especially in the hills and pollution free environment supported by appropriate connectivity – both physical and IT connectivity, is an ideal place to set up data centers.

CHAPTER 3 – INCENTIVES

Incentives Provided by Govt. of India under the National Electronics Policy (NEP) 2012

1. **Financial Incentives under M-SIPS:** Based on this Policy, Electronic products manufacturing units shall be provided incentive for 20% of capex for SEZ based units and 25% of capex plus reimbursement of excise/ CVD on capital equipment for non-SEZ based units. Thresholds for investments in the Electronics unit have been defined in the M-SIPS 2012 notification of MOC-IT.
2. **Financial Assistance for Greenfield and Brownfield EMCs:**
 - (a) For greenfield EMCs, financial assistance will be provided for up to 50% of project cost, limited to INR 50 Crores for every 100 acres of land
 - (b) For expansion/upgradation of brownfield EMCs, financial assistance will be provided up to 75% of the project cost, limited to INR 50 Crores
3. **Development of Electronics Manufacturing Clusters by MSMEs:**
 - (a) Reimbursement of expenses of diagnostic study for Greenfield or Brownfield EMCs – INR 2.50 Lakhs/cluster.
 - (b) Reimbursement of expenses incurred for soft interventions will be 75% of the sanctioned amount of the project cost in the DPR, limited to INR 2.5 Lakhs/cluster.
 - (c) Reimbursement of expenses incurred for preparing Detailed Project Report (DPR) – INR 5 Lakhs/cluster
4. **Preferential Market Access:** The policy of GoI on preferential market access in Government procurement for domestically manufactured electronics products shall be implemented in all Government of Uttarakhand departments. Special preference shall be given to Uttarakhand-based manufacturers.
5. **Reimbursement of Expenses for Testing and Certification Required for Export for MSMEs:**
 - (a) Reimbursement of testing charges incurred for getting the products tested from any lab domestic/abroad, subject to the testing charges incurred for getting the products tested at STQC labs as per prevailing rates of test charges levied by STQC labs. The maximum reimbursement under the scheme would be limited to INR 75,000/-.
 - (b) Reimbursement of 25% charges towards the annual certification fee paid to any certification body (domestic/abroad) per model at actual, subject to:
 - (i) Up to INR 50,000/- for one model.
 - (ii) Up to two certifications and each model would qualify only once under the scheme.
6. **Reimbursement of expenses relating to compliance with "Indian Standards for MSMEs:**
 - (a) Reimbursement of actual testing charges subject to the testing charges incurred for getting the products tested at STQC labs (for initial registration as well as during surveillance) as per prevailing rates of test charges levied by STQC labs. The maximum reimbursement under the scheme would be limited to INR 75,000/-.
 - (b) Reimbursement of actual test charges received by BIS for Registration (Max. INR 25,000/-).

7. Skill Development:

- (a) To facilitate skill development in the Electronics sector focusing on youth to increase their employability to work in 'Manufacturing' and 'Service support' functions, a 'Scheme for Financial Assistance to Telangana for Skill Development' has been approved by GoI.
- (b) The scheme provides for 75 % of training fee as assistance for training courses identified by Electronics Sector Skills Council, Telecom Sector Skills Council and NIELIT.
- (c) The scheme also provides for 100% fee reimbursement to 40% of the seats which would be reserved for the candidates belonging to SC/ST/Economically weaker sections.
- (d) Further, Registration-cum-Certification fee per candidate (for the first attempt only) would also be reimbursed to assessing/certifying agencies.
- (e) A target of 15,000 (3000 per year) candidates for Uttarakhand has been set to benefit from this scheme

8. Promoting R&D and Announcement of National Awards:

- (a) GoI has targeted to increase the number of PhDs to 3,000 over a period of 5 years with 100% funding by the GoI.
- (b) To recognize the achievements in the Electronics industry, to motivate the entrepreneurs in the sector and to encourage new investments and innovation in the sector, GoI has constituted various national awards with budget of more than INR 3.5 Crores.

Division of Regions

9. Categorization of various regions in the State of Uttarakhand has been defined as per Uttarakhand Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Policy 2015 where in the State has been divided into four categories for the purpose of quantum of incentives/subsidies as under:

Category	Regions Included
Category A	Whole Districts of Pithoragrah, Uttarkashi, Chamoli, Champawat, Rudraprayag and Bageshwar.
Category B	<ul style="list-style-type: none"> Whole Districts of Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Almora All hilly development blocks of District Dehradun other than Vikasnagar, Doiwala, Sahaspur and Rajpur. All hilly development blocks of District Nainital other than Haldwani and Ramnagar.
Category C	<ul style="list-style-type: none"> Regions located above 650 mtrs from sea level of Raipur, Sahaspur, Vikasnagar and Doiwala development blocks of District Dehradun. Ramnagar and Haldwani development blocks of District Nainital.
Category D	<ul style="list-style-type: none"> Whole Districts of Haridwar and UdhamSingh Nagar Remaining area of District Dehradun and Nainital (which are not included in category 'B' and 'C').

Note : The categorization of above regions would remain same for ICT&E Policy 2016

Incentives provided by Uttarakhand State

Fiscal Incentives

10. Various Fiscal incentives proposed to be provided by the State are enumerated below. Also shown in the table below is the applicability of these incentives to "New Industry", "Existing Industry" and "Expansion Industry" (existing industry undergoing capacity expansion). If an existing company not in IT Sector, sets up an IT venture, or an existing IT company sets up a new line of business in the sector, it would be considered as a 'New Industry' as per this policy.

Sl. No.	Incentive proposed	New	Existing	Expansion
1.	Capital Subsidy (Equipment, Plant & Machinery)	✓	×	✓
2.	Captive Equipment Subsidy (Power Generation System)	✓	×	✓
3.	Land cost	✓	×	✓
4.	Stamp duty exemption	✓	✓	✓
5.	Tax (VAT) subsidy	✓	×	✓
6.	Interest on Loan subsidy	✓	×	×
7.	Electricity Subsidy	✓	✓	✓
8.	Effluent Treatment Plants (ETP)	✓	×	✓
9.	Patent Filing Subsidy	✓	✓	✓
10.	Use of Natural Measures	✓	✓	✓
11.	Employment Generation	✓	✓	✓
12.	Incentive for State BPO/KPO Industry on Connectivity Charges	✓	×	✓
13.	Incentive for State Govt. ICT&E procurements/tenders (only for Companies with HQs in Uttarakhand)	✓	✓	✓
14.	Installation of Mobile Towers	✓	×	×

11. The details of various Fiscal incentives proposed to be provided for the industry in various regions of the State are listed in the table below :

Incentives under ICT&E Policy					
Sl. No.	Subsidy	Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
1.	Capital Subsidy (Equipment, Plant & Machinery)	45% (Max. up to ₹ 45 Lacs)		35% (Max. up to ₹ 35 Lacs)	
2.	Captive Equipment Subsidy (Power Generation System)	20% for all Categories (Additional 10% subsidy will be awarded on-use of natural resources like Solar, Wind or Hybrid systems)			
3.	Land Cost Subsidy (Only for Govt. Land)	50% (irrespective of size of the project)		Large Projects (₹ 50&75 cr.) : 15% Mega Projects (₹ 75-200 cr.) : 25% Ultra-Mega Projects (>₹ 200 cr.) : 30%	
4.	Stamp Duty Exemption	100%			
5.	VAT@	100% for first 5 years & 90% thereafter		100% for first 5 yrs & 60% thereafter	
6.	Interest Subsidy on Loan	12% (Max up to ₹ 10 lacs/yr/unit)		8% (Max up to ₹ 6 lacs/yr/unit)	
7.	Electricity Subsidy (on Electricity Duty)	100% for first 10 yrs thereafter 80%		50% for first 10 yrs and thereafter Nil	
8.	Effluent Treatment Plants (ETP)	one time capital subsidy up to 50% of the cost of ETP subject to a ceiling of ₹ 50 Lacs			
9.	Patent Filing	Domestic Patent : ₹ 5 lacs International Patent : ₹ 10 lacs (Only for Companies having their HQs in Uttarakhand)			
10.	Use of Natural Measures	Rain Water Harvesting : 50% of cost (max ₹ 2 Lacs) Waste Water Recycling : 50% of cost (max ₹ 5 Lacs)			
11.	Employment Generation	For 3 yrs (Max)	For 2 yrs (max)	For 1 yrs (max)	Nil
11A.	Note	₹ 700 p.m/male employee & ₹ 1 000 p.m for female/EWS/SC/ST drawing max salary of ₹ 15,000 subject to employee strength exceeding the Specified Threshold of Direct Employees			
12.	Incentive for State BPO/KPO Industry on Connectivity Charges	50% for first 3 yrs	30% for first 2 yrs	Nil	Nil
13.	Incentive for State Govt. ICT&E procurements/tenders (only for Companies with HQs in Uttarakhand)	10% price preferential			
14.	Installation of Mobile Towers	Cat A: 100% rebate on Govt. charges Cat B: 50% rebate on Govt. charges			

Note :

@--The unit can deposit the tax for the first quarter and reimbursement of net VAT would be credited at the end of the quarter, subject to its adjustment depending upon actual incident of taxation.

Non Fiscal Incentives

12. The State Government shall generate an investor friendly environment in the State and shall ensure :

- (a) Preferential allotment of land for ICT industry and ESDM Industry in the State.
- (b) E-District Managers (EDMs)/any other official/appointment nominated by the IT Department would be the Nodal Officers for each District in the State. He would act as a single window official for resolution and monitoring of ICT & E Industry related issues within the District.
- (c) Continuous/uninterrupted power supply to ICT and ESDM industries.
- (d) Dedicated additional feeders would be provided both to Greenfield and Brownfield EMCs to ensure guaranteed uninterrupted power supply 24×7.
- (e) Lending in ICT and ESDM shall be considered as priority sector loaning by State Level Financial Institutions.
- (f) Special efforts to develop high quality social infrastructure like schools, housing, health, entertainment and leisure facilities in ICT and ESDM industry locations.
- (g) Providing and enabling administration system for obtaining easy clearances & approvals from various Government Departments.
- (h) The ESDM units shall be exempted from inspections/certifications from various Acts and Rules administered by the Labour Department of the State Government. Any administration of labour laws by the Department should be in prior consultation with the Industry stakeholders.

Infrastructure Support

13. The State shall endeavor to attract these high technology industries by leveraging :

- (a) Its strength : a cool and picturesque locale, abundant water, competitive real estate prices, qualified HR, skilled IT workforce, proactive administration and developing an infrastructure to improve air, rail, road and telecommunication connectivity.
- (b) Uttarakhand is well connected to the National Capital through Air, Rail and Road Transport having two functional airports (at Dehradun & Pant Nagar), nine major railway stations and 20 bus stations.
- (c) Uttarakhand is also having well-developed Integrated Industrial Estates (IIEs), IT Parks and growth centers at various well approachable locations in Uttarakhand like Haridwar, Pant Nagar, Dehradun etc. In addition to existing IT Park at Dehradun, the State Government would set up additional IT Park at Ram Nagar/Pant Nagar. In addition, it is also proposed to setup ICT Hubs and ESDM Hubs at all major cities in the state.
- (d) The Government will aggressively identify potential investors as part of a planned approach and will present Uttarakhand's value proposition in the specific context of their businesses.
- (e) The Government will attempt to attract the knowledge industry to Uttarakhand by providing the necessary infrastructure for ICT education and skill development in ESDM.
- (f) The Government will ensure that all clearances to set up a new business will be done on top most priority.
- (g) The Government will support workshops/seminars on IT with industry participation.

CHAPTER 4 - MONITORING AND EXECUTION

1. It is imperative to note that the success of any policy purely depends on its implementation. However, It has been seen that there is tremendous resistance to change within Government establishments. Hence there is a need to set timelines for various activities for holistic implementation of this policy. These targets and milestones need to be reviewed on a regular basis. To ensure successful implementation of this policy in letter and spirit, following is proposed:

- (a) Information Technology Dept., State of Uttarakhand shall function as the Nodal Agency for all IT Initiatives of the state.
- (b) IT Department will do benchmarking of the departments to identify the current state of e-Governance in the departments and create an IT roadmap for the departments. IT cell of the department shall implement the roadmap.
- (c) In the implementation of the various e-Governance Projects, the State Government will set up a Project Monitoring Unit, which will work closely with Independent Software Developers / Vendors / system integrators, Back end Departments of the Government, under the supervision of the Nodal Agency.
- (d) After launching of the e-Governance project, the Departmental head will submit a complete report on the learning and recommendations.
- (e) Surveys will be periodically undertaken to assess the level of acceptance of any initiative. This would throw up alerts indicating the need for course corrections in the strategy options and implementations.
- (f) The Government would examine the cost savings on account of the newer forms of service delivery and how such savings could be passed on to the end users.
- (g) Through mass media publicity and special incentives for transacting online, the Government would actually be encouraging the use of ICT.

Annexure-A

Categories of Industries included in the scope / definition of IT/ITeS Industry**1. Computing devices including:**

- (a) Desktop
- (b) Personal Computer
- (c) Servers
- (d) Work-station
- (e) Nodes
- (f) Terminals
- (g) Network P.C.
- (h) Home P.C.
- (i) Lap-top Computers
- (j) Note Book Computers
- (k) Palm top Computer / PDA

2. Network Controller Cards / Memories including:

- (a) Network Interface Card (NIC)
- (b) Adaptor – Ethernet / PCI / EISA / Combo / PCMCIA
- (c) SIMMs – Memory
- (d) DIMMs – Memory
- (e) Central Processing Unit (CPU)
- (f) Controller – SCSI / Array
- (g) Processors – Processor / Processor Power Module / Upgrade

3. Storage Units including:

- (a) Hard Disk Drives / Hard Drives
- (b) RAID Devices & their Controllers
- (c) C.D. ROM Drives
- (d) Tape Drives – DLT Drives / DAT
- (e) Optical Disk Drives
- (f) Other Digital Storage Devices

4. Others: Key Board, Monitor, Mouse and Multi-media Kits**5. Printers and Output Devices including:**

- (a) Dot matrix
- (b) LaserJet
- (c) Inkjet
- (d) Deskjet
- (e) LED Printers
- (f) Line Printers
- (g) LED TV
- (h) Plotters
- (i) Pass-book Printers

6. Networking products including:

- (a) Routers
- (b) Switches

- (c) Concentrators
- (d) Trans-receivers

7. Software including:

- (a) Application Software
- (b) Operating system
- (c) Middleware / Firmware
- (d) Anti-Virus Software

8. Power supplies to Computer Systems including:

- (a) Switch mode power supplies
- (b) Uninterrupted Power supplies

9. Networking / Cabling & related accessories (related to IT Industry)

- (a) Fiber Cable
- (b) Copper Cable
- (c) Cables
- (d) Connectors, Terminal Blocks
- (e) Jack panels, patch cord
- (f) Mounting cord / wiring blocks
- (g) Surface mount boxes

10. Consumables including:

- (a) C.D. ROM / Compact Disk
- (b) Tapes DAT / DLT
- (c) Ribbons
- (d) Toners
- (e) Inkjet Cartridges
- (f) Inks for Output devices

11. Electronic Components:

- (a) Printed Circuit Board / populated PCB
- (b) Printed Circuit Board / PCB
- (c) Transistors
- (d) Integrated Circuits / ICs
- (e) Diodes / Thyristor / LED
- (f) Resistors
- (g) Capacitors
- (h) Switches / (On / Off, Push button, Rocker, etc.)
- (i) Plugs / sockets / relays
- (j) Magnetic heads, Print heads
- (k) Connectors
- (l) Microphones / Speakers
- (m) Fuses
- (n) Electronic Displays
- (o) Micro Motors
- (p) Transformers
- (q) Major IoT constituents like sensors, transducers and actuators.
- (r) Bio-metric systems, RFIDs, etc.
- (s) LED Light

12. Telecommunication Equipment including:

- (a) Telephones
- (b) Videophones
- (c) Facsimile machines / Fax cards
- (d) Tele-Printers / Telex machine
- (e) PABX / EPABX / RAX / MAX – Telephone Exchange
- (f) Multiplexers / Muxes
- (g) Modems
- (h) Telephone answering machines
- (i) Telecommunication Switching Apparatus
- (j) Antenna & Mast
- (k) Wireless Datacom equipment
- (l) Receiving equipment like Pagers, Mobile / Cellular Phones, etc.
- (m) VSATs
- (n) Video Conferencing Equipment
- (o) Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.
- (p) Mobile Phone and its accessories

13. Consumer Electronics and Appliances**14. IT Enabled Services:**

- (a) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:

- (i) Delivered outside India
- (ii) Delivered over communication networks, and
- (iii) Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

- (b) Services which would not be included are:

- (i) Remote production/manufacturing units
- (ii) The Corporate offices of companies or their local branches
- (iii) Virtual business on Internet.

- (c) Following services which meet the above criteria would be included:

- (i) Back-Office Operations
- (ii) Call Centers/BPO/KPO
- (iii) Content Development or Animation
- (iv) Data Processing
- (v) Engineering and Design
- (vi) Geographic Information System Services
- (vii) Human Resource Services
- (viii) Insurance Claim Processing
- (ix) Legal Database
- (x) Medical Transcription
- (xi) Payroll
- (xii) Remote Maintenance
- (xiii) Revenue Accounting
- (xiv) Supports centers and
- (xv) Web-site Services.

By Order,

DEEPAK KUMAR,

Secretary

कार्मिक अनुभाग-1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

30 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 2936/XXX-1-2016-12(42)/2001-भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान ₹ 37,400-67,000+ग्रेड पे ₹ 8,700 में नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम/आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3
1.	डा० बी० वी० आर० सी० पुरुषोत्तम-2004	01.01.2017 (प्रोफॉर्मा पदोन्नति)
2.	श्री रमन रविनाथ-2004	01.01.2017

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2017 ई0 (माघ 08, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

03 नवम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 1850/लाईसेंस-निलम्बन/2016-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	नवीन कुमार पुत्र श्री भानू राम, निवासी ग्राम बक्कोट, तह० डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़	UK-0520120005165, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/पी०एस०वी० (TR)/भार वाहन ट्रांस (TR), वैधता 04.06.2017	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
2.	निर्मल चन्द पुत्र श्री हीरा बल्लम, निवासी गड़सारी, चम्पावत	UK-0420030100843, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/जी०वी० कैब/एल०एम०वी० कैब (TR), वैधता 29.10.2017	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
3.	प्रकाश पुत्र श्री जगत नाथ, निवासी म० नं० 112, नौगवानाथ, तह० खटीमा, ऊ०सि० नगर	UK-0320100002834, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 03.01.2019	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, चाणक्य पुरी सर्किल, दिल्ली	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	निलम्बन अवधि
4.	ज्योति रोहित पाण्डे पुत्र श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे, निवासी बूम रेंज, टनकपुर	UK-0320130015678, मो० साइकिल (NT), वैधता 12.06.2033	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बॉसवाड़ी, बैंगलौर, कर्नाटक	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
5.	अशोक पुत्र श्री कैलाश, निवासी म० नं० 35, ग्राम चौडाडुमखुरी, जिला चम्पावत	UK-0320130015772, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ पी०एस०वी० बस, ट्रांस (TR), वैधता 04.01.2019	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, चाणक्य पुरी सर्किल, दिल्ली	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
6.	विजय कुमार पुत्र श्री शंकर राम, निवासी ग्राम चौकी, खर्ककाढी, जिला चम्पावत	UK-0320140018702, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ पी०एस०वी० बस, ट्रांस (TR), वैधता 30.11.2018	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मयूर विहार सर्किल, दिल्ली	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
7.	इस्लाम हुसैन पुत्र श्री हामित खॉं, निवासी ग्राम मनहारगोठ, पो० टनकपुर, चम्पावत	UK-0320070015070, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ जी०वी० कैब/एल०एम०वी० कैब (TR), वैधता 24.04.2019	प्रभारी निरीक्षक, यातायात, चम्पावत	दिनांक 03.11.2016 से दिनांक 02.02.2017
8.	देवराम पुत्र श्री रुद्र राम, निवासी ग्राम काकड़, पो० बाराकोट, जिला चम्पावत	UK-0320120011792, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT), वैधता 26.08.2032	मा० न्यायाधीश, मैट्रो पोलिटिन साकेत कोर्ट द्वारा निलम्बित (छः माह हेतु)	दिनांक 27.11.2015 से छः माह हेतु निलम्बन प्रभावी
9.	भूपाल सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी अल्लाहवर्दी, पो० नौगवानाथ, खटीमा, ऊ०सि० नगर	UK-03-20100003270 हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT), वैधता 12.07.2028	मा० न्यायाधीश, मैट्रो पोलिटिन साकेत कोर्ट द्वारा अनर्ह (छः माह हेतु)	दिनांक 25.07.2015 से प्रभावी
10.	अभिषेक सबरवाल पुत्र श्री राजीव कुमार, निवासी वार्ड नं० 9, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320120012648, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT), वैधता 21.10.2032	मा० न्यायाधीश, मैट्रो पोलिटिन द्वारिका कोर्ट द्वारा अनर्ह	छः माह हेतु निलम्बित, तत्काल प्रभाव से लागू
11.	कमल सिंह पुत्र श्री मान बहादुर, निवासी म० नं० 12, लाल इमली पड़ाव, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320080022633, हल्का मोटर वाहन (TR)/ट्रांस/पी०एस०वी० बस (TR), वैधता 31.07.2016	मा० न्यायाधीश, मैट्रो पोलिटिन साकेत कोर्ट द्वारा निलम्बित (दो माह हेतु)	दिनांक 18.07.2016 से प्रभावी (अनर्ह)
12.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी बमनपुरी, पो० चन्दनी बनबसा, चम्पावत	UK-03/9764/TNK/09, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT), वैधता 08.10.2029	मा० न्यायाधीश, साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट द्वारा अनर्ह (छः माह हेतु)	दिनांक 30.01.2016 से प्रभावी
13.	प्रकाश चन्द्र गड़कोटी पुत्र श्री बेनी राम गड़कोटी, निवासी रावलगाँव रैगाँव, लोहाघाट, चम्पावत	UK-0320080014000, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ हल्का यात्री/भार वाहन/ट्रांस (TR), वैधता 12.02.2013 से 11.02.2016	मा० न्यायाधीश, पी०एस०सी०, नई दिल्ली कोर्ट द्वारा अनर्ह (छः माह हेतु)	दिनांक 22.04.2015 से प्रभावी

नोट:—मा० न्यायालय द्वारा निलम्बित/अनर्ह लाइसेंस (Disqualified DL)अवमुक्त दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही लाइसेंस अवमुक्त/नवीनीकरण किया जायेगा।

कार्यालयादेश

17 दिसम्बर, 2016 ई०

पत्रांक 2013/लाइसेंस-निलम्बन/2016-निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

क्र० सं०	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	निलम्बन अवधि
1.	दिनेश सिंह महारा पुत्र श्री दीवान राम, मोन० 24, थुवा मेहरा, पो० कर्णकरायत, लोहाघाट, चम्पावत	UK-0520110004890, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/पी०एस०बी० (TR)/भार वाहन ट्रांस (TR), वैधता 07.11.2016 (TR)	ट्रैफिक पुलिस, मयूर विहार सर्किल, दिल्ली-91	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
2.	सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीश प्रसाद, ग्राम गलचौड़ा, तह० लोहाघाट, जिला चम्पावत	UK-0320110008397, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/पी०एस०बी० (TR), वैधता 10.11.2017	ट्रैफिक पुलिस, जहाँगीरपुरी सर्किल, दिल्ली	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
3.	दलीप सिंह पुत्र श्री त्रिलोक, ग्राम चम्पापुर बनबसा, पो० चंदनी, जिला चम्पावत	UK-0320100002834, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ट्रांस (TR)/पी०एस०बी० बस (TR), वैधता 06.06.2019	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जहाँगीरपुरी सर्किल, दिल्ली (NT)	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
4.	अनिल कुमार पुत्र श्री हेमन्त कुमार, ग्राम ज्ञानखड़ा, टनकपुर, चम्पावत	UK-03/7765/TNP/2008 मो० साइकिल एवं हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 31.10.2028	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, कल्याणपुरी सर्किल, दिल्ली	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
5.	दीवान राम पुत्र श्री मनी राम, निवासी वार्ड नं० 3, टनकपुर, चम्पावत	UK-032090001844, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 26.09.2016	परिवहन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
6.	आनंद सिंह पुत्र श्री खीम सिंह, निवासी लोहाघाट, चम्पावत	UK-0320110006172, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 10.12.2018	ट्रैफिक इंस्पेक्टर, आई०जी०आई० सर्किल, दिल्ली	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
7.	चन्द्र शेखर मिश्रा पुत्र श्री महेश चन्द्र, निवासी ग्राम छिनीगोट, पो० टनकपुर, जिला चम्पावत	UK-03200100002226, हल्का मोटर वाहन व मो० साइकिल (NT), वैधता 24.03.2030	प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर, चम्पावत	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017
8.	आशीष बिष्ट पुत्र श्री अमर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम कर्णकरायत, जिला चम्पावत	UK-0320120011792, हल्का वाहन, मो० साइकिल (NT), वैधता 06.01.2016 से 05.01.2036	पुलिस अधीक्षक, चम्पावत	दिनांक 17.12.2016 से दिनांक 16.03.2017

रश्मि भट्ट,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
मोटर वाहन विभाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

22 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्र संख्या 1040/सा0 प्रशा0/नोटिस/2016-17-वाहन संख्या यू0के0 12टीबी-0812 (ऑटोरिक्षा) का चालान दिनांक 24.11.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन में स्वीकृत 09 के सापेक्ष 13 सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री जयकृष्ण पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद, निवासी ग्राम परिन्दा, पो0 जयहरीखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0-1520000013772 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1001/सा0प्रशा0/लाई0 नोटिस/2016-17, दिनांक 25.11.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 20.12.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0-1520000013772 को दिनांक 21.12.2016 से दिनांक 05.02.2017 तक 45 दिवसों की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

22 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्र संख्या 1041/सा0 प्रशा0/नोटिस/2016-17-वाहन संख्या यू0के0 12पीबी-8888 (सवारी वाहन) का चालान दिनांक 11.06.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, रुद्रप्रयाग ने वाहन में स्वीकृत 35 के सापेक्ष 43 सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, रुद्रप्रयाग ने वाहन चालक श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पातल, पो0 पछाली, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0-1520030016640 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 640/सा0प्रशा0/लाई0 नोटिस/2016-17, दिनांक 05.09.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 21.12.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0-1520030016640 को दिनांक 22.12.2016 से दिनांक 21.02.2017 तक दो माह की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

आदेश

23 दिसम्बर, 2016 ई०

पत्र संख्या 1042/सा० प्रशा०/नोटिस/2016-17-वाहन संख्या यू०के० 15 टीए-0296 (मैक्सी कैब) का चालान दिनांक 23.11.2018 को प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश ने वाहन में 02 सवारी ओवरलोड, चालक कक्ष में 03 सवारी बैठी पाई गई, खतरनाक संचालन, चालक द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश ने वाहन चालक श्री जगमोहन सिंह नेगी पुत्र श्री शेर सिंह नेगी, निवासी ग्राम दुर्गापुर, पो० निम्बूचौड, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या डी०एल०-0320040534597 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1099/सा०प्रशा०/लाई० नोटिस/2016-17, दिनांक 15.12.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 22.12.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा-1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या डी०एल०-0320040534597 को दिनांक 22.12.2016 से दिनांक 21.03.2017 तक तीन माह की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

28 दिसम्बर, 2016 ई०

पत्रांक 2508/टी०आर०/पंजी०नि०/UP21-8778/2016-वाहन संख्या UP21-8778 (TRUCK), मॉडल 1994, चेसिस संख्या 360324HVQ002509 तथा इंजन नं० 697023GVQ120435, कार्यालय में श्री आजाद खान पुत्र श्री सज्जाद नवी, निवासी म० नं० 108, बघौरी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 23.12.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 27.12.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP21-8778 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324HVQ002509 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 दिसम्बर, 2016 ई०

पत्रांक 2509/टी०आर०/पंजी०नि०/UP02-3305/2016-वाहन संख्या UP02-3305 (TRUCK), मॉडल 1990, चेसिस संख्या 344073336905 तथा इंजन नं० 692D01347335, कार्यालय में मौ० ताजुद्दीन पुत्र श्री मौ० याकूब, निवासी म० नं० 238, नकहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 23.12.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 27.12.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02-3305 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073336905 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2510/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02-3413/2016-वाहन संख्या UP02-3413 (TRUCK), मॉडल 1973, चेसिस संख्या 3440023704166 तथा इंजन नं0 692D013704171, कार्यालय में श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम शान्तिपुरी, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.12.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 22.12.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP02-3413 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 3440023704166 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2528/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CA-3146/2016-वाहन संख्या UK06CA-3146 (TRAILER), मॉडल 2011, चेसिस संख्या 11UK06012081, कार्यालय में श्री हरजिन्दर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी म0 नं0 185, साधुनगर, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 24.12.2016 को आवेदन-पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2016 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु दिनांक 27.12.2016 की आख्या पत्रावली में संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-3146 (TRAILER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK06012081 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

ऊधमसिंह नगर।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी, 2017 ई0 (माघ 08, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन-आदि

कार्यालय नगर पंचायत, लक्सर, जनपद हरिद्वार

उपविधि, 2016 नगर पंचायत, लक्सर

09 जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 515/उपनियम न0प0/2016-17-नगर पंचायत, लक्सर, हरिद्वार सीमान्तगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा 2 के खण्ड (झ) तथा (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2013 बनायी जाती है; उत्तर प्रदेश में जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, निम्न उपविधि से नियन्त्रित होंगे।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

1. यह उपविधि नगर पंचायत, लक्सर, हरिद्वार की "नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, लक्सर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ :

- (i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;
- (ii) "उपविधि" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;
- (iii) "नगर पंचायत" से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत से है;

- (iv) "अधिशाली अधिकारी" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1968 के अधीन नियुक्त अधिशाली अधिकारी से है;
- (v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत नगर पंचायत, लक्सर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशाली अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;
- (vi) "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत अधिशाली अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशाली अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है;
- (vii) "नियम" से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है;
- (viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है;
- (ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;
- (x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है;
- (xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" का अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे-प्लास्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि;
- (xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग-निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो;
- (xiii) "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;
- (xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्बलित है;
- (xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction waste)" से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;
- (xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

- (xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है;
- (xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है;
- (xix) "नगर पंचायत प्राधिकारी (Municipal Authority)" में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;
- (xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)" का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है;
- (xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;
- (xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of Facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;
- (xxiii) "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है;
- (xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है;
- (xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आबारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोक जा सके;
- (xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।
5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर-पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय-समय पर संशोधित करी जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिये जायेंगे।
8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा।
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।
14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक-यूजर-चार्जस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पंचायत/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य-दिवस में नगर पंचायत/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसका गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी। यह वृद्धि बोर्ड स्वीकृति के अधीन होगी।
16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक-अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है तो प्रथम बार ₹ 200, द्वितीय समय ₹ 500 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,000 पेनल्टी देनी होगी।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500, द्वितीय समय ₹ 1,000 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,500 की पेनल्टी देनी होगी।
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि 2016 में निर्धारित अग्रसारित यूजर चार्जस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची-1

सेवा शुल्क (User Charges)

क्र० सं०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रति माह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में			
		जैविक-अजैविक कूड़ा अलग-अलग पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक-अजैविक कूड़ाघर/श्रोत पर ही अलग-अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	05	10	07	10
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	10	18	15	20
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	15	20	20	25
4.	सब्जी एंव फल विक्रेता	50	75	60	100
5.	रेस्टोरेन्ट	150	200	175	225
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	150	200	175	225
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बारातघर	350	400	450	500
9.	बैंकरी	100	150	125	175
10.	कार्यालय	25	30	40	50
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	50	70	60	75
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	10	20	15	25
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	100	150	125	175
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	50	75	60	100
15.	दुकान	25	50	40	60
16.	फैक्ट्री	200	400	300	450
17.	वर्कशॉप/कबाड़ी	100	135	125	150

1	2	3	4	5	6
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	25	35	30	50
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	500

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनर्चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैसाइट/कार बैटरी
घरेलू झाड़े से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला साफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के काँच/धातु/खड़, लकड़ी, फाईल, पुड़िया ट्रेटोपैक, कैसेट कम्प्यूटर, डिस्कट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे, इन्जेक्शन सुई तथा सिरिज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट तथा छोटे फ्लोरोसेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, ग्रीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जिसके लिए कम से कम ₹ 500 एवं अधिक से अधिक ₹ 5,000 का अर्थदण्ड होगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500 प्रतिदिन होगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लक्सर में अन्तिम रूप में निहित होगा।

एस0 पी0 जोशी,

अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत, लक्सर,

हरिद्वार।

राम सिंह,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, लक्सर,

हरिद्वार।

सूचना

मेरे पति के सैन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम कमा सिंह अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम कमला बाराथोकी है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय।

समस्त विधिम औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

प्रार्थिनी,

श्रीमती कमला बाराथोकी,

पत्नी ले०क० आर० एस० बाराथोकी,

निवासी-8-353 हीरानगर,

हल्द्वानी-263139,

जिला-नैनीताल (उत्तराखण्ड)